



खबरों की उड़ान

बुधवार 26 मार्च 2025
वर्ष - 3, अंक - 329
पृष्ठ - 12
उत्तराखण्ड
मूल्य - 3 रुपये

जनादेश एक्सप्रेस

अखबार नहीं आंदोलन



www.janadeshexpress.in

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली से प्रकाशित

दीपिका ने भारतीय फिल्मों और टैलेंट

संक्षिप्त

खबरें

प्लाट बेचने की डील कर हड़प लिए 16.54 लाख रुपये

देहरादून (आर एन एस)। मांडुवाला, प्रेमनगर स्थित प्लाट बेचने की डील कर एक व्यक्ति 16.54 लाख रुपये हड़प लिए गए। तहरीर पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सुनील सिंह बिष्ट निवासी कुजापुरी विहार, अजबपुर ने एसएसपी कार्यालय में तहरीर दी। बताया कि वह मई 2023 में अपने परिवार के साथ दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे। आशुतोषनगर, ऋषिकेश में उनके माता-पिता के घर के सामने रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर केदार सिंह रावत मूल निवासी नयागांव, डुंडा उत्तरकाशी और मशरुफ निवासी देवत्राष्ट्रि कॉलोनी, देहरादून, पटेलनगर ने उन्हें एक प्लॉट दिखाया। जो मांडुवाला है। आरोपियों ने बताया कि यह जमीन मशरुफ ने खरीदी हुई है। उसका एक एग्रीमेंट भी दिखाया। जमीन खरीदने की डील होने पर पीड़ित ने 31 जुलाई 2023 को चेक से 4.50 लाख रुपये और 29 सितंबर 2023 को 5.50 लाख रुपये नगद देकर एग्रीमेंट कराया। इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग समय पर कुल 6.54 लाख रुपये ले लिए।

वित्त विधेयक 2025 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित

नई दिल्ली। लोकसभा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के प्रावधानों में संशोधन के लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को स्वीकार करते हुए वित्त विधेयक 2025 मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही 2025-26 के बजट को पारित करने की प्रक्रिया पर सदन की मोहर लग गई है। वित्त विधेयक को अब चर्चा तथा वापसी के लिए राज्यसभा में भेजा जाएगा जहां उस पर मात्र औपचारिक चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं की सालाना 12 लाख रुपये की आय पूरी तरह से करमुक्त होगी और उससे थोड़ा अधिक आय पर कर का प्रभाव सीमित रहेगा। उन्होंने गूल और मेटा कंपनियों पर ऑनलाइन विज्ञापन की आय पर लगने वाले छह प्रतिशत की दर के इकालाइन करने को हटाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख से अधिक की थोड़ा अधिक आय पर लगने वाला कर बढ़ी हुई आय पर ही लगाया जाएगा और वह बढ़ी हुई आय तक ही सीमित होगा।

नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपियों को बड़ी राहत, घर तोड़ट्टे पर कोर्ट ने लगाई रोक

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिंसा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन की कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए उसे फटकार भी लगाई है। फहीम खान और यूसुफ शेख की संपत्तियों को गिराने पर हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न किए जाने पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि, अदालत का आदेश पारित होने से पहले ही सोमवार दोपहर को फहीम खान की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है। आज ही नगर निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में फहीम खान के दो मंजिला मकान को अवैध बताते हुए गिरा दिया था।

अधिकारियों के अनुसार, महल इलाके में स्थित आरोपी यूसुफ शेख के मकान के अवैध हिस्से को भी दहा दिया गया है। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के

अभय कुमार

नैनीताल जिले के रामनगर के सांवल्दे क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बना कन्वेंशन सेंटर आज वीरान पड़ा है। सेंटर अब जंगल में तब्दील होता नजर आ रहा है। यहां बने भवन सरकारी सिस्टम की उदासीनता और लापरवाही की तस्वीर बयां कर रहे हैं। आखिर क्यों इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट को शुरू करने में सरकार नाकाम रही? क्यों 5 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिला? इसकी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया था उद्घाटन बता दें कि रामनगर के सांवल्दे में 5 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की केंद्र वित्त पोषित योजना के तहत कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था, जो आज लावारिस हालत में पड़ा हुआ है।

बीती 13 जनवरी 2021 को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे जनता को समर्पित किया था। 4 साल बीत चुके हैं और अब तक यह एक बार भी उपयोग में नहीं लाया गया। अब ये कन्वेंशन सेंटर चारों ओर से झाड़ियों से घिर गया है। सरकार की योजना थी शानदार इस सेंटर



को जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों, कॉर्पोरेट मीटिंग एवं सेमिनार्स के लिए विकसित किया जाना था। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलता और पर्यटन को बढ़ावा मिलता, लेकिन हकीकत ये है कि अफसरों की बेरुखी और सरकारी अनदेखी के चलते यह इमारत बस एक खंडहर बनकर रह गई है, जिसे लेकर राज्य आंदोलनकारी ने सरकार को घेरा है। उम्मीद थी कि इससे क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब तो ये किसी भूतहा जगह जैसा लगने लगा है। सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन अब इसे देखने तक नहीं आ रहे।

इससे अच्छा तो इस पैसे को किसी और विकास कार्य में लगा देते. - प्रभात ध्यानी, राज्य आंदोलनकारी-

राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि करोड़ों रुपये की लागत से बना यह सेंटर जंगल में तब्दील हो गया है। सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए। ताकि, इसे फिर से उपयोग में लाया जा सके और स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिल सके। कन्वेंशन सेंटर का निर्माण काफी साल पहले किया गया था। जिसे लेकर टेंडर की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन कोई भी आवेदक नहीं आया। अब एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ताकि,

- रामनगर में जंगल में तब्दील हुआ 5 करोड़ का कन्वेंशन सेंटर !

- डीएम साहब एक नजर कन्वेंशन सेंटर पर भी करोड़ों रुपये लगा करके ऐसे भवन का क्या औचित्य जो देखरेख नहीं होने के कारण होती जा रही खंडहर इससे अच्छा तो यह होता की सरकार इन पैसे का उपयोग बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आयम तैयार करने में लगाती



इस कन्वेंशन सेंटर को उपयोग में लाया जा सके. -

-अतुल भंडारी, जिला पर्यटन अधिकारी-

जंगल में तब्दील होते इस कन्वेंशन सेंटर को लेकर यही सवाल उठता है कि जब करोड़ों की लागत से इतनी बड़ी परियोजना बनाई गई थी, तो उसके संचालन की ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई? क्या सरकार सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है? अगर वाकई

इस सेंटर को फिर से शुरू किया जाना है तो आखिर कब?

अक्सर ऐसा ही होता है सरकारी योजनाओं का हथ्थ करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, भव्य उद्घाटन होता है और फोटो खिंचवाए जाते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे सब भुला दिया जाता है। अब यह कन्वेंशन सेंटर भी उसी सरकारी उदासीनता का शिकार होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली ये होगी कि क्या इस बार सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

दिल्ली की सीएम ने पेश किया 1 लाख करोड़ रुपये का बजट

नई दिल्ली। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। यमुना और सीपेज की सफाई के लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144

हजार करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही। दिल्ली की सीएम ने प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए 320 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। दिल्ली सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार वैकल्पिक हेल्थ केयर की दिशा में भी काम करेगी।

इसके लिए आयुष पर जोर दिया जाएगा। सीएम रेखा ने कहा- मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहती हूं कि आज तक की सरकारों के राज में 2023 में 78 हजार 800 करोड़ का बजट था। 24-25 का बजट घटकर सिर्फ 76 हजार करोड़ रह गया। ये दिल्ली में सबसे खराब स्थिति थी। इस बार का दिल्ली का बजट एक लाख करोड़ रुपये का है। ये ऐतिहासिक है।

उन्होंने कहा कि मैं बजट पेश कर रही हूं। आज का बजट साधारण नहीं है। दिल्ली की जनता और पूरा देश सदन के माध्यम से बजट सुन रहा है। दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनदेश लेकर यहां आई है। इस सरकार का पहला बजट कैसा होगा, आज यहां पूरा देश देख रहा है। ये बजट पिछले 10 साल से बेहाल हुई दिल्ली को संभालने का पहला कदम है।

चार धाम यात्रा: सब कुछ अनुकूल, हर स्तर पर तैयारी तेज

पीएम के गैंड प्रमोशन और बढ़ी हुई यात्रा अवाधि से हर कोई उत्साहित

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए हर स्तर पर तैयारी तेज हो गई है और उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखवा और हर्षिल आने के बाद से यात्रा के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चार धाम यात्रा दस दिन पहले शुरू हो रही है। यानी कि इस बार यात्रा के लिए ज्यादा दिन उपलब्ध होंगे। यात्रियों के स्तर पर पंजीकरण के लिए दिखाए जा रहे उत्साह को देखते हुए सरकार ने भीड़ प्रबंधन को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू कर दी है।

गैंड प्रमोशन, देवभूमि है लोगों की पहली पसंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा और पर्यटन स्थल हर्षिल के दौरे से यात्रा के लिए अच्छा माहौल तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री छह मार्च को उत्तराखंड आए थे। ऐसा पहली बार हुआ, जब कि चार धाम यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हुआ। भले ही औपचारिक कार्यक्रम शीतकालीन यात्रा को लेकर था, लेकिन प्रधानमंत्री ने चार धाम यात्रा की



भी भरपूर ब्रांडिंग की। देश को यह तक बतलाया कि पिछले दस वर्षों में चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कितना बड़ा अंतर आ गया है।

30 अप्रैल से यात्रा, इस बार ज्यादा दिन चलेगी

वर्ष 2024 में चार धाम यात्रा का शुभारंभ दस मई को हुआ था। इस बार उसकी शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। वर्ष 2023 में यात्रा 22 अप्रैल को शुरू

हो गई थी और रिकॉर्ड 56,18,497 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। वर्ष 2024 में कम दिन मिलने और प्राकृतिक आपदा की घटनाओं के बावजूद यात्री संख्या के आंकड़े ने सबको चौंका दिया था। इस वर्ष यात्रा में कुल 48,04,215 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे।

चार धाम यात्रा, कब कहां के कपाट खुलेंगे

30 अप्रैल को गंगात्री-यमुनोत्री

- पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दस दिन पहले शुरू हो रही यात्रा - पीएम नरेंद्र मोदी के मुखवा-हर्षिल दौरे से बना है जबरदस्त माहौल

02मई को केदारनाथ धाम 04मई को बद्रीनाथ धाम सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड की यात्रा व्यवस्था ने देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है और उनका भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा का भरपूर प्रमोशन किया है। हम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए संकल्पबद्ध हैं। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

राज्यपाल की अध्यक्षता में राज्य बाल कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड की 16वीं आम सभा की बैठक हुई सम्पन्न

देहरादून(आरएनएस)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) की अध्यक्षता में मंगलवार को राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड की 16वीं आम सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद को आज की आवश्यकता के अनुरूप नई योजनाओं को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि परिषद को अपने वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना होगा। राज्यपाल ने परिषद को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाए जाने एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ नई योजनाओं को शामिल किए जाने हेतु सचिव रविनाथ रामन एवं चंद्रेश कुमार यादव को बैठक कर शीघ्र रोडमैप तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य बाल कल्याण परिषद को आर्थिक रूप से मजबूत करने, नई योजनाओं को शामिल करने और परिषद के उद्देश्यों की सही मायने में पूर्ति किए जाने हेतु अभिनव कार्ययोजना तैयार किए जाने की नितान्त आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि बाल कल्याण परिषद को बच्चों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने संसाधनों

और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। इसके अभाव में कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से वंचित



नहीं रहना चाहिए।

राज्यपाल ने बच्चों को आत्मनिर्भर, सशक्त और कुशल बनाए जाने के लिए बाल कल्याण परिषद द्वारा नयी सोच और नए विचारों को अपनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की प्रतिभा को पहचानते हुए, उन्हें कुशल जनशक्ति तैयार करने पर अधिक ध्यान देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि आज का

समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है। हमें बाल कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करनी होंगी,

कहा की बाल कल्याण एक ऐसा विषय है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सहयोग हेतु तत्पर है। परिषद को आमजन तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। बाल कल्याण के लिए जनमानस से संपर्क साधते हुए सदस्यों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि करनी होगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने परिषद में उत्कृष्ट योगदान दे रहे सदस्यों की सराहना भी की। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद के वर्ष 2024-25 के अनुमानित आय एवं व्यय का अनुमोदन करने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर अपनी सहमति दी। महासचिव पुष्पा मानस ने आम सभा की 15वीं बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि व अनुमोदन प्राप्त किया और विगत वर्ष में किए गए क्रियाकलापों और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

बैठक में सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, सचिव चन्द्रेश कुमार यादव, वित्त नियंत्रक राज्यपाल डॉ. तुषि श्रीवास्तव, उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश बाबला, उपाध्यक्ष मधु बेरी, कोषाध्यक्ष डॉ. आशा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव कमलेश्वर प्रसाद भट्ट, रेडक्रॉस के कोषाध्यक्ष मोहन खत्री सहित परिषद के विभिन्न पदाधिकारी, सदस्य व जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थित थे।

आधुनिक तकनीकी और बेहतर प्रबंधन संग करें 2027 कुंभ की तैयारी: डीजीपी

देहरादून(आरएनएस)। कुंभ मेला 2027 में आधुनिक तकनीकी और बेहतर प्रबंधन रखने का निर्देश डीजीपी दीपम सेठ ने दिया है। मंगलवार को सरदार पटेल भवन में पुलिस अफसरों संग कुंभ मेला व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने पूर्व में हुए कुंभ मेलों की पुलिस व्यवस्था, निर्माण कार्य और अन्य पहलुओं का प्रेजेंटेशन दिया। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। यातायात विभाग विस्तृत ट्रैफिक प्लान बनाए, संचार विभाग प्रभावी संचार प्रणाली तैयार करें। फायर सर्विस अग्नि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें। प्रशिक्षण विभाग पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण दें। एसडीआरएफ, बम डिस्पोजल टीम, जल पुलिस भी अपनी तैयारियों की समीक्षा कर लें। डीजीपी ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनन्द भरणे, निदेशक यातायात नारायण सिंह नपलच्याल, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप, पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था धीरेंद्र गुज्याल शामिल रहे।

रोडवेज कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता संशोधित हो

देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता दर संशोधित करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा कि परिवहन निगम ने जुलाई 2022 में शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कर्मचारियों को पुनरीक्षित मकान किराया भत्ते का लाभ देने की मांग उठाई गई थी, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता देने की मांग उठाई है।

गढ़ी कैट में सीवरेज योजना की मंजूरी पर जताया आभार

देहरादून(आरएनएस)। गढ़ी कैट क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सीवरेज की समस्या के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। शहरी विकास विभाग की ओर से वहां सीवरेज योजना को मंजूरी के बाद मंगलवार को स्थानीय लोगों ने कैप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका आभार जताया।वहीं कैबिनेट मंत्री ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया। गढ़ी कैट क्षेत्र में सीवरेज योजना के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के तौर पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम ने टपकेश्वर महादेव मंदिर, गढ़ी, डाकरा, छावनी क्षेत्र में 9 एमएलडी का एसटीपी, 3 एमएलडी का एसपीएस, 0.16 एमएलडी सह-उपचार संयंत्र तथा आईएंडडी के साथ सीवर लाइन और मैनहोल्स का कार्य किया जाना प्रस्तावित किया है। इस परियोजना की कुल लागत रुपये 53.72 करोड़ है, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में रुपये 14.58 करोड़ जारी कर दी गयी है। इस परियोजना के तहत 10.5 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) की क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र और सीवरेज सुविधाओं का विकास किया जाएगा, इससे क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत मिलेगी। प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने आशा जताई कि कार्य जल्द से जल्द प्रारम्भ कर क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यूपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का एक अप्रैल को प्रदेश भर में प्रदर्शन

देहरादून(आरएनएस)। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने एक अप्रैल को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। केंद्र सरकार की यूनिकाइड पेंशन स्कीम को एक अप्रैल से लागू करने पर कड़ा एतराज जताया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने दिल्ली तक पैदल यात्रा से सकुशल लौटने के बाद कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है। नई पेंशन स्कीम को बंद करने की जगह अब यूपीएस को लाकर सरकार कर्मचारियों को धोखा दे रही है।

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा कि कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। यदि सरकार जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। अभी तक आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही चलाया जा रहा है। यूपीएस

के विरोध में एक अप्रैल को पूरे प्रदेश में यूपीएस का पुतला दहन किया जाएगा। सभी कर्मचारी अपने कार्यालयों में यूपीएस



के खिलाफ काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करेंगे। प्रदेश महामंत्री सीता राम पोखरियाल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के नाम पर

बांटने का काम कर रही है। किसी भी हाल में यूपीएस को उत्तराखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष नरेश

के बीच दूरियां बढ़ने के साथ साथ कर्मचारियों का सरकार के प्रति रोष भी बढ़ रहा है। शहीद स्थल पर ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में सोहन सिंह रावत, मुकेश बहुगुण, लक्ष्मण सजवाण, माखन लाल शाह, आशुतोष सेमवाल, अरविंद चौहान, नरेंद्र पटवाल, गुड्डि मट्टड़ा, विनोद चौहान, राकेश भट्ट, आशीष जोशी आदि मौजूद रहे।

भट्ट ने कहा कि पेंशन की लड़ाई अब अंतिम दौर पर पहुंच गई है। जिस प्रकार सरकार कर्मचारियों की मांग को अनदेखा कर रही है, उससे सरकार और कर्मचारियों

आंचल को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि होली के दिन अनिरुद्ध पीड़िता के फ्लैट पर नशे की हालत में पहुंचा। पीड़िता का कहना है कि जब उसने वहां से जाने की बात कही तो अनिरुद्ध ने उसे अपनी पत्नी को तलाक देने और शादी करने का झांसा दिया। जब आंचल ने विरोध किया तो अनिरुद्ध ने



उसके पेट में बोटल मार दी और सिर दीवार पर दे मारा। हमले में पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि अनिरुद्ध ने उसका फोन भी छीन लिया। ताकि, वह किसी को सूचना न दे सके। किसी तरह वह नीचे पहुंची तो पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद, आंचल पुलिस थाने पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। एसएसआई रायपुर भरत सिंह रावत ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर अनिरुद्ध, उसकी पत्नी और माता के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

संपत्ति हड़पने के आरोप में शहर कोतवाली में तीन आरोपियों पर मुकदमा



अहमद ने दोबारा संपत्ति का स्वामित्व अपने नाम स्थानांतरित करवाने के लिए आवेदन दिया। नगर निगम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर पीड़िता को पता चला कि तीन जनवरी 2003 को बनाए गए एक फर्जी एग्रीमेंट जरिए फजीवाड़ा किया गया। गुलशन बेगम ने आरोप लगाया कि जमीर अहमद, सगीर अहमद और नसीर अहमद ने मिलकर फर्जी विक्रय

पत्र 8 अप्रैल 2004 दर्ज कराया। नगर निगम के रिकॉर्ड में हेराफेरी कर संपत्ति को अपने नाम दर्ज करा लिया। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने नसीर अहमद, जमीर अहमद और सगीर अहमद के खिलाफ फर्जीवाड़े से संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज किया है। शहर कोतवाल सीबीएस अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।



मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एचपीसी में विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दिया

देहरादून(आरएनएस)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील प्रोजेक्ट पर सत, समावेशी एवं जलवायु अनुकूल विकास पर्यटन विकास से सम्बन्धित एचपीसी (उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की अध्यक्षता करते हुए नई टिहरी में 54.05 करोड़ रु० की डीपीआर लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी तथा 37.11 करोड़ रूपए के सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट तथा वेस्ट मेनेजमेंट सेंटर, 1.46 करोड़ की डीपीआर लागत वाले महादेव मंदिर व 2.33 करोड़ की डीपीआर लागत वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एचपीसी की बैठक में मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही सीएस ने प्रोजेक्ट कार्मिकों के लिए टीए/डीए भत्तों सहित



महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव पर भी अनुमोदन प्रदान किया। मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा

ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर

सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला, ललित मोहन ख्याल सहित वित्त, पर्यटन तथा जिलाधिकारी टिहरी उपस्थित थे।

देहरादून-हरिद्वार टोल प्लाजा पर दर्दनाक हादसा



देहरादून(आरएनएस)। देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर सोमवार सुबह एक भयानक हादसा हुआ। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बेकाबू डंपर ने तीन कारों को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद यह खंभे से टकरा गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार सुबह देहरादून-हरिद्वार की ओर जा रहे डंपर (यूके18सीए6636) का लच्छीवाला टोल

प्लाजा के पास ब्रेक फेल हो गया। डंपर ने अनियंत्रित होकर 03 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर टोल प्लाजा के पोल से टकरा गया। डंपर की चपेट में आने से 02 वाहन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और एक वाहन (यूके07एएफ2506) डंपर और पोल के बीच फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस कार में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों

को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और मोर्चरी में भिजवाया गया। मृतकों में से एक व्यक्ति की पहचान रतनमणि उनियाल निवासी इंद्रप्रस्थ एनक्लेव रायपुर देहरादून के रूप में हुई है। दूसरे मृतक के पास से पंकज कुमार पुत्र किशोरी लाल पवार के नाम का पहचान पत्र मिला है, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है।

इंदिरा हृदयेश की जयंती पर लगाया नेत्र जांच शिविर

देहरादून(आरएनएस)। प्रदेश की पूर्व मंत्री व नेता प्रतिपक्ष रहीं कांग्रेस की दिवंगत नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की 84वीं जयंती पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित की गई। मुख्यालय सभागार में अमृतसर आई अस्पताल की ओर से मुफ्त आंखों की जांच का शिविर लगाया गया। जिसमें 80 मरीजों ने आंखों की जांच करवाई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोपी, देवेन्द्र सिंह, गिरिराज किशोर हिंदवाण, गरिमा मेहरा दसौनी, प्रतिमा सिंह, सुजाता पॉल, विकास नेगी, आनंद सिंह पुंडीर, विनीत भट्ट बट्ट, मंजू त्रिपाठी, सुलेमान, दिनेश सिंह कौशल, युद्धवीर पंवार आदि मौजूद रहे।

ग्राफिक एरा ने विश्व टीबी दिवस पर निकाली जागरूकता रैली

देहरादून(आरएनएस)। ग्राफिक एरा के एमबीबीएस के छात्र-छात्राओं ने विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये यह रैली निकाली। जिसमें एबीबीएस के शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने शेरपुर गांव में जाकर लोगों को टीबी के रोकथाम, लक्षणों और उपचार के कोर्स को पूरा करने के लिये लोगों को जानकारी दी। रैली का नेतृत्व नोडल अधिकारी डॉ. नेहा उपाध्याय ने किया। रैली में प्रो. डा. सचिन पालवे, डा. काजल गुप्ता, डा. अमित जून, डा. अभिनव, डा. सुधा स्पंदना और डा. अमित मित्तल मौजूद रहे। इस अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

बेसिक शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण शुरू हो: डायट प्रशिक्षित

देहरादून(आरएनएस)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से डीएलएड प्रशिक्षितों ने सरकार से बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग की। सोमवार को प्रशिक्षितों के प्रतिनिधिमंडल ने ननूरखेड़ा स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक अजय कुमार नौडियाल से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। अनुपम ने कहा कि विभाग में वर्तमान में बेसिक शिक्षक के काफी पद रिक्त हैं। इन पदों को जल्द भरने के लिए सरकार को शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण जल्द शुरू करना चाहिए। इससे स्कूलों को शिक्षक मिलेंगे और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर और बेहतर हो जाएगा। निदेशक ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कहा कि इस बाबत जल्द सरकार को प्रस्ताव को भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में डीएलएड प्रशिक्षित सोनाली, किरण, स्वाति, कैलाश, राहुल अंकित, विवेक, अभिषेक आदि शामिल रहे।

टीबी उन्मूलन के लिए हर गांव, शहर में स्क्रीनिंग कैप : धन सिंह

देहरादून(आरएनएस)। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला टीबी मुक्त राज्य बनेगा। इसके लिए हर गांव और शहर में स्क्रीनिंग कैप आयोजित किए जाएंगे और रोगियों की पहचान का लक्ष्य रखा गया है। विश्व टीबी दिवस पर सोमवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के सापेक्ष उत्तराखंड अभी टॉप थ्री राज्यों में चल रहा है और जल्द ही राज्य को पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य को टीबी मुक्त करने के लिए पहले दो सालों से प्रयास चल रहे हैं और अभी तक पांच हजार के करीब गांवों को टीबी मुक्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से हर गांव, शहर और बार्ड में स्क्रीनिंग कैप आयोजित किए जाएंगे और टीबी रोगियों की पहचान कर उन्हें निशुल्क इलाज दिया जाएगा।

कल्याण कोष से छह पत्रकार आश्रितों को आर्थिक सहायता

देहरादून(आरएनएस)। पत्रकार कल्याण कोष एवं मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना समिति की महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह पत्रकार आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की गई है। पत्रकार कल्याण कोष के कुल 11 प्रकरणों पर विचार किया गया, जिनमें छह मामलों में 30 लाख आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की गई। इसमें हाल ही में दिवंगत पत्रकार मंजुल माजिला के परिवार को भी समिति ने आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की है। महानिदेशक तिवारी ने बताया जिन प्रकरणों के दस्तावेज अपूर्ण पाए गए, उन्हें एक मौका देते हुए संबंधित जिलों के जिला सूचना अधिकारियों से आवेदन पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगली बैठक में इन निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत एक मामला रखा गया, लेकिन जरूरी दस्तावेज न होने से इसे भी अगली बैठक में रखा जाएगा। समिति के निर्णय का अंतिम अनुमोदन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री करेंगे। बैठक में अपर निदेशक आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक केएस चौहान और समिति के सदस्य मौजूद रहे।

यूसीसी पोर्टल पर मार्च तक अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण का विरोध

देहरादून(आरएनएस)। राजकीय कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर मार्च माह तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने विरोध किया है। इस संबंध में परिषद की ओर से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आदेश को रद्द कराने की मांग की गई है। जिसमें कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों के लिए यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराए जाने के शासन के आदेश के विरुद्ध कतिपय जिलों के जिलाधिकारियों ने इसे एक निश्चित समय सीमा में बांध दिया है। जिसमें मार्च तक अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पंजीकरण नहीं कराने की दशा में ही मार्च माह का वेतन जारी नहीं करने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है।

कल तक जो जनप्रतिनिधि भ्रष्ट था, आज उसे संरक्षण दे रही सरकार: गरिमा

देहरादून(आरएनएस)। चमोली जिला पंचायत में प्रशासक पद पर नियुक्ति को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। यहां प्रशासक पद पर नियुक्ति को लेकर निर्वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच खींचतान जारी है। इस मुद्दे पर सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी राज में सुचिता और पारदर्शिता का कितना ख्याल रखा जा रहा है, इसकी बानगी चमोली में देखने को मिल रही है। जिस रजनी भंडारी पर नंदा राजजात यात्रा में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए भाजपा की सरकारों ने लगातार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और रजनी भंडारी के कार्यकाल की जांच बैठाई। आज वही सरकार रजनी भंडारी के पति राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने के बाद उनकी सबसे बड़ी पैरोकार और संरक्षक बन गई है।

पेंशन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सेवानिवृत्त कर्मचारी

हल्द्वानी(आरएनएस)। ईपीएस-95 के मुद्दे पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यूनतम पेंशन 7500 करने समेत अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। इसके बाद कर्मचारियों ने ईपीएफओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रास्ता जाम किया। बाद में कमिश्नर ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा। शीघ्र ठोस कदम न उठाने पर आंदोलन को चेताया। सोमवार को समिति अध्यक्ष राजेंद्र कुमार वालिया के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांगों को लेकर पहले रैली निकाली। इसके बाद सभी कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ धरना-प्रदर्शन किया। समिति के प्रांतीय समन्वयक जगत सिंह डोबाल ने कहा कि लंबे समय से वह लोग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। वक्ताओं ने कहा कि न्यूनतम



पेंशन 7500 और डीए के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा, छूटे हुए कर्मचारियों को ईपीएफ का सदस्य बनाने, सरकार की ओर से 1995 में दी गई सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।

यहां भारतीय खाद्य निगम, वन विकास चिकित्सा सुविधा, छूटे हुए कर्मचारियों को ईपीएफ का सदस्य बनाने, सरकार की ओर से 1995 में दी गई सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए।

अध्यक्ष पान सिंह नेगी, भूपेंद्र अधिकारी, बृज मोहन सिजवाली, किरण पंत, मधुसूदन लोहनी, कमलापति सनवाल, कैलाश गुरुरानी, गणेश मेलकानी आदि ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया।



स्वयंसेवकों ने ग्राम कटारपुर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली

हरिद्वार(आरएनएस)। एचईसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स की एनएसएस इकाई के शिबिर में स्वयंसेवियों ने कटारपुर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इसके बाद ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में स्वयंसेवियों ने ड्राइंग और रंगोली बनाई। साथ ही मतदाता जागरूकता पर नुक्कड़ नाटिका का मंचन किया। इसमें संजना भट्ट, सोनिया, उमंग, पर्व, कनक, तनु ने भाग लिया। पोस्टर मेकिंग में आरुष तोमर, विशाखा, नेहा, रंगोली में सौम्या शर्मा, सृष्टि ने भाग लिया।

घरों में गंदा बद्बूदार पानी आने से परेशान लोग

हरिद्वार(आरएनएस)। ज्वालापुर के धीरवाली क्षेत्र में मंगलवार को लोग घरों में सीवर के गंदा बद्बूदार पानी आने से परेशान रहे। दिन में लोगों को घर पर नल से साफ पीने का पानी नहीं मिला। गंदे पानी की सप्लाई होने से लोगों पर बीमार होने का खतरा बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि गंदे पानी की समस्या का समाधान कर साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। ज्वालापुर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदे प्रदूषित पानी की सप्लाई होने की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में गंदे पानी की सप्लाई होने की समस्या बनी रहती है। मंगलवार को भी धीरवाली क्षेत्र में लोग घर में गंदे पानी की सप्लाई होने से परेशान रहे। स्थानीय निवासी पिकेंद्र, प्रदीप, तरुण, संजीव आदि का कहना है की घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। लगातार समस्या बनी रहती है।

देहरादून की युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप, युवक ने कराया मुकदमा

हरिद्वार(आरएनएस)। एक युवक ने देहरादून की युवती पर दोस्ती करके ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई है। कनखल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सर्वप्रिय विहार निवासी हिमांशु सेमवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह नोएडा में एक कंपनी में कार्यरत है। अप्रैल 2022 में एक ऑनलाइन डेटिंग एप पर उसकी मुलाकात समीना खान निवासी देहरादून से हुई थी। बातचीत होने पर समीना ने दिल्ली आकर उससे मुलाकात की थी। उसके बाद वह उसके काफी नजदीक आ गई। आरोप है कि कि मना करने के बावजूद भी मुलाकात करने पहुंचती रही और उसे डरा धमकाकर नजदीकी बढ़ाती रही। आरोप है कि उसे ब्लैकमेल कर रुपये मांगे जाने लगे। विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी गई।

किशोरी लापता, युवक पर अपहरण का आरोप

हरिद्वार(आरएनएस)। सिडकुल से एक किशोरी संदिग्ध लापता हो गई। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए क्षेत्र के रावली महदूद निवासी व्यक्ति ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बहन 22 मार्च को घर का सामान लाने के लिए निकली थी लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। बहन के वापस न लौटने पर मोबाइल फोन चेक करने पर पता चला कि हिमांशु निवासी ग्राम पिरचिरा गोटीया थाना खुदागंज जिला शहाजहांपुर उससे अक्सर बातचीत करता था। आरोप है कि युवक उसकी बहन को बहला-फुसलाकर ले गया है। एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

आरोपी वाहन चालक की तलाश तेज

हरिद्वार(आरएनएस)। नगर कोतवाली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत होने के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दुर्घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में पुलिस जुट गई है। पीड़ित नीलम निवासी पांदापुर जिला मुरादाबाद यूपी ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसके पति रणजीत सिंह उम्र 40 वर्ष पुत्र जयप्रकाश 13 फरवरी की रात सप्तऋषि चुंगी के सामने रोड क्रॉस कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उन्हें एक अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। परिणामस्वरूप उसके पति की मौत के पर ही मौत हो गई थी। चालक मौके से वाहन लेकर फरार होने में कामयाब रहा था। कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि वाहन चालक की तलाश कर रहे हैं।

पूर्व विधायक की बेटी को ब्लैकमेल करने का आरोपी दबोचा

हरिद्वार(आरएनएस)। पूर्व भाजपा विधायक की बेटी को आपत्तिजनक फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने के मामले में हरकत में आई रानीपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। इधर, मामले में नामजद दूसरी आरोपी पूर्व विधायक की पत्नी होने का दावा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर की भूमिका को लेकर जांच जारी है। दो दिन पूर्व पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका पत्नी सोमिल चौधरी निवासी टिहरी विस्थापित कालोनी गली नंबर छह हाल निवासी सी-77 शास्त्री नगर ज्वालापुर ने कोतवाली रानीपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि होली के दिन उसके एक परिचित युवक राघव ने उससे मोबाइल फोन पर संपर्क साधकर होली की शुभकामनाएं दी थी। उसके बाद युवक के अभद्रता करने पर उसने कॉल काट दी थी।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

हरिद्वार(आरएनएस)। चंद्राचार्य चौक क्षेत्र के एक सैलून में कार्यरत एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर कोतवाली ज्वालापुर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्यामपुर क्षेत्र की एक युवती पिछले कई साल से एक सैलून में कार्यरत है। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि उसकी मुलाकात दिसंबर 2022 से अतुल मिश्रा पुत्र सरवेस कुमार निवासी, नेवादा मसूरपुर जिला सीतापुर यूपी से हुई थी। आरोप है कि धीरे-धीरे नजदीकी बढ़ाकर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ शादी कर लेगा।

भाजपा ओबीसी मोर्चा ने नव नियुक्त जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा का किया भव्य स्वागत

हरिद्वार(आरएनएस)। ओबीसी मोर्चा की ओर से भाजपा जिला कार्यालय पर नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार ने आशुतोष शर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि आशुतोष शर्मा सरल व्यक्तित्व के प्रतिभाशाली भाजपा नेता हैं जिन्होंने विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया है। उनके नेतृत्व में जिला भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में जनपद हरिद्वार की समस्त विधानसभाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी।

पथरी में गौकशी करने पर दंपति और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार(आरएनएस)। बुढ़ाहेड़ी गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 150 किलो प्रतिबंधित मांस और गौकशी करने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की भनक लगने के बाद अभी आरोपी मौके से भाग निकले। मामले में पुलिस ने दंपति समेत छह लोगों के खिलाफ गोवंश अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश देने में लगी है। पुलिस के अनुसार सोमवार को मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम बुढ़ाहेड़ी में कुछ लोग गौकशी को अंजाम देने में लगे हैं। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर छापेमारी की लेकिन पुलिस की भनक लगते ही गौकशी कर रहे लोग मौके से भाग निकले। पुलिस ने मौके से 150 किलो गोमांस व गौकशी करने के उपकरण बरमाद किये जिन्हें सील किया गया है। साथ ही मौके से मिले गोमांस के सेम्पल को फॉरेंसिक जांच के लिये भेजा गया है।

ऊर्जा निगम के अवर अभियंता से मारपीट, पुलिस प्रोटेक्शन की मांग

हरिद्वार(आरएनएस)। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में ऊर्जा निगम के अवर अभियंता रामकुमार के साथ मारपीट के मामले में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन की मंगलवार को अधीक्षण अभियंता प्रदीप कुमार चौधरी के साथ रोशनाबाद कार्यालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि अब



जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को सील किया



हरिद्वार(आरएनएस)। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को सील कर दिया है। हरिद्वार की तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि

हरिद्वार में स्थित इन मदरसों का टीम ने निरीक्षण किया और पाया कि ये सभी का पंजीकरण नहीं था। इसके बाद पांचों मदरसों को अफसरों ने सील कर दिया। हरिद्वार की तहसीलदार प्रियंका ने बताया कि पांच



प्रेस क्लब चुनाव के लिए 30 ने लिए नामांकन

हरिद्वार(आरएनएस)। प्रेस क्लब चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तीन और महासचिव पद के लिए दो सदस्यों ने नामांकन पत्र लिए। इकार्यकारिणी सदस्य के लिए 20 पदों के लिए 25 नामांकन पत्र लिए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप गर्ग ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने वालों में अध्यक्ष पद के लिए धर्मेन्द्र चौधरी, अश्वनी अरोरा और राजकुमार, महामंत्री पद के लिए दीपक मिश्रा और नवीन चौहान ने नामांकन पत्र लिए। कार्यकारिणी सदस्य के लिए 25 सदस्यों ने नामांकन पत्र लिए। इनमें परविंदर कुमार, संदीप शर्मा, विकास झा, मयूर सैनी, काशीराम सैनी, सुभाष कपिल, बृजपाल



सिंह, नरेश गुप्ता, मुकेश वर्मा, बालकृष्ण शास्त्री, संजय चौहान, रामकुमार शर्मा, अमित कुमार गुप्ता, सुनील पाल, संदीप रावत, महेश पारीक, डॉ हिमांशु द्विवेदी, आशु शर्मा, आनंद गोस्वामी, विकास

चौहान, श्रवण कुमार झा, सुनील कुमार मिश्रा, संजय रावल, तनवीर अली और राधिका नागरथ शामिल हैं। इस अवसर पर सहायक चुनाव अधिकारी मनोज कुमार खन्ना और संजीव शर्मा मौजूद थे।

अधिकारी ऐसे क्षेत्र में नहीं जाएंगे जहां पर उनके साथ झगड़ा होने की संभावना है। पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है तो उसे क्षेत्र में उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली करने के लिए जाया जाएगा। अन्यथा नहीं। रामकुमार की ओर से अधीक्षण अभियंता को पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया करने का पत्र दिया गया है। अधीक्षण अभियंता ने इस पत्र को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजकर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है।

गंगा के जल को शुद्ध रखना सामूहिक जिम्मेदारी

हरिद्वार(आरएनएस)। डॉ. आदित्य कुमार मौर्य ने कहा कि गंगा नदी न केवल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़ी हुई है। गंगा के जल को शुद्ध रखना, उसकी पवित्रता को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉ. मौर्य राजकीय महाविद्यालय मरगुबपुर की ओर से रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय दल्लवाला में नमामि गंगे अभियान के तहत गोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने गंगा के संरक्षण और शुद्धता की आवश्यकता पर जोर दिया। नोडल अधिकारी डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और अन्य मानवीय गतिविधियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की।

संक्षिप्त

खबरें

प्रावि के वार्षिकोत्सव में तोली योग की प्रस्तुति ने तालियां बटोरी

नई टिहरी (आरएनएस)। पीएम प्राथमिक विद्यालय तहसील का प्रथम वार्षिकोत्सव सोमवार को रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, केंद्रीय संस्कृत संस्थान देवप्रयाग के निदेशक प्रो पीवीबी सुब्रह्मण्यम व नगर पालिका अध्यक्ष ममता देवी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। विधायक ने पीएमश्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय तहसील के लिए दो स्मार्ट बोर्ड और तीन लाख के लागत के दो फेब्रिकेटेड रूम देने की घोषणा की। स्कूल प्रांगण में आयोजित वार्षिक उत्सव सरस्वती वंदना से शुरू हुआ। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने गीत, नृत्य व नाटक की विभिन्न प्रस्तुतियां दीं। जिनमें गढ़वाली नृत्य नाटिका बम बम भोले, तोली योग (गीत और योग का मिश्रण) गंगा के महत्व, अरुणाचली नृत्य, सहित नई कक्षा में आने पर लिस्परिंग के बारे में नाटक ने तालियां बटोरीं।

प्रो. एम. एम. सेमवाल बने गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। गढ़वाल विवि में राजनीति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एमएम सेमवाल ने सोमवार को विवि के मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार, प्रो. सेमवाल को अगले तीन वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती प्रो. राकेश चंद्र सिंह कुंवर से विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, अन्य अधिकारी एवं शिक्षक उपस्थित रहे और उन्होंने प्रो. सेमवाल को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

हादसे में दिल्ली के युवक की मौत के मामले में केस दर्ज

ऋषिकेश (आरएनएस)। पांच दिन पहले सिंगटाली में एक सड़क हादसे में दिल्ली के युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुनिकीरीती पुलिस के मुताबिक अतुल कुमार ढक्कर, निवासी राधेपुरी, दिल्ली ने शिकायत देकर बताया कि उनका बेटा किशन ढक्कर 18 मार्च को बस से ऋषिकेश पहुंचा था। यहां किराये पर एक स्कूटी ली और अगले दिन वह देवप्रयाग के लिए निकल गया। इसी बीच बदरीनाथ हाईवे पर सिंगटाली के नजदीक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि अज्ञात वाहन की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।

चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार

ऋषिकेश (आएनएस)। रायवाला बाजार में सर्विस रोड से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर युवक से 93 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी की पहचान सत्री उर्फ भाटिया, निवासी बादशाहपुर पथरी हरिद्वार के रूप में हुई। थानाध्यक्ष बीएल भारती के मुताबिक आरोपी के खिलाफ एनडीएफपीएस ऐक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेशी के बाद कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अतिरक्षित में जेल भेज दिया है।

शीशमझाड़ी से किशोरी लापता

रिषिकेय। शीशमझाड़ी से एक किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन चार दिन बाद भी उसका कोई सुरा नहीं लगा। जिसके बाद परिजन शिकायत लेकर मुनिकीरती थाने पहुंचे। तहरीर पर पुलिस ने किशोरी की गुमशुदाई दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पिता ने शिकायत में बताया कि उनकी 16 साल की बेटी बीती 19 मार्च को दोपहर में घर से पहचान संबंधी दस्तावेज और नगदी लेकर निकली थी, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटी। थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। जल्द ही उसे बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा।

ग्रामीणों को सेब के पौध और चारा किट बांटी

उत्तरकाशी। गोविंद वन्य जीव विहार पार्क प्रशासन की ओर से केट प्लान के तहत सोमवार को रुपिन एवं सुपिन रेंज के जलागम क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को सेब के पौध एवं चारा किट वितरित की गई। वनक्षेत्र के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की। परियोजन कर ग्रामीणों को उनके रख रखाव की जानकारी दी। सोमवार को वन विश्राम भवन नेटवाड़ में आयोजित गोष्ठी के दौरान वन क्षेत्राधिकारी सुपिन रेंज गौरव कुमार अग्रवाल द्वारा सुपिन रेंज और रुपिन रेंज के कोट गांव, देवरा, गैंचवाण गांव, मसरी, ग्वाल गांव, दौषी, नैटवाड़, कलाप, सुनचवाण गांव, हलटाडी आदि गांवों के ग्रामीणों को 3500 से अधिक सेब पौध और 28 लाभार्थियों को चारा किट वितरित किए गए। इस अवसर पर निवर्तमान ग्राम प्रधान देवरा, जयदेव नौटियाल और वन सरपंच नूरुनु, उपेन्द्र सिंह आदि स्थानीय ग्रामीणों सहित वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

निबंध प्रतियोगिता में बबीता राणा रही प्रथम

कोटद्वार (आरएनएस)। बर्फिया लाल जुवांठ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुरोला के इतिहास और समाजशास्त्र विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें इतिहास विभाग की छात्रा बबोता राणा व समाज शास्त्र विभाग की अर्चना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोमवार को महाविद्यालय परिसर में घरेलू हिंसा, युवाओं में बढ़ता हुआ नशा एवं समाज पर उसका प्रभाव और भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

ऋषिकेश विधानसभा में आयोजित हुआ वृहद बहुउद्देशीय शिविर

ऋषिकेश (आरएनएस)।
उत्तराखण्ड सरकार के तीन साल पूर्ण होने के उपलक्ष में प्रदेश में 'जन सेवा' कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा ऋषिकेश में सोमवार को क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में वृहद बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के स्टाल लगाकर लोगों की समस्याएं का निस्तारण किया गया। नगर निगम ऋषिकेश के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्र विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार के यह तीन वर्ष सेवा, सुशासन और विकास के रहे हैं। उन्होंने तीन वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन वर्ष में सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां आईं, लेकिन सरकार ने धरातल पर जाकर उसका समाधान किया। डा. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का संकल्प लिया है, उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्तराखण्ड पूरी सामर्थ्य से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी), भू-कानून, नकल विरोधी, दंगा नियंत्रण जैसे कानून जनहित में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण सहित लखपति दीदी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से मातृ शक्ति के कल्याण के लिए ठोस कदम आगे बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने उनके अध्यक्षता में बनी पर्वत समिति की रिपोर्ट के आधार पर आंदोलनकारियों के लिए दस फीसदी श्रैक्षित आरक्षण की व्यवस्था की है। प्रवासी उत्तराखण्डियों के सम्मेलन के माध्यम से प्रवासियों को राज्य के साथ



जोड़ा गया।

डा. अग्रवाल ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य का पूरा देश में 13वां स्थान पर आना सुखद संकेत है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो या जी-20 बैठकों का आयोजन उत्तराखण्ड को इन आयोजनों से दूरगामी लाभ मिला है। सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में देश में पहला स्थान महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष में राज्य का सालाना बजट एक लाख करोड़ को पार कर जाना बताता है कि चुनौतियों के बावजूद हम सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं।

डा. अग्रवाल ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़ी सफलता की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा, शीतकालीन यात्रा समेत राज्य के कई स्थानों पर पहुंचकर पर्यटन विकास में अभूतपूर्व योगदान किया।

इस अवसर पर राज्य महिला
आयोग के अध्यक्ष कसूम कंडवाल, मेयर

शंभू पासवान, निवर्तमान ब्लाक प्रमुख
भगवान सिंह पोखरियाल, मंडल अध्यक्ष
सुमित पवार, सुरेंद्र कुमार, नगर आयुक्त
शैलेंद्र नेगी, अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी
डीएस गोसाई, पूर्व मेयर अनीता ममगाई,
जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कविता शाह,
उप जिलाधिकारी स्मृता परमार, संदीप
गुप्ता, दीपक धमीजा, चंद्र मोहन
पोखरियाल, इंद्र कुमार गोदवानी, रुचि
जैन, राजकुमारी पंत, पुनीता भंडारी,
सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट,
पार्षद अशु डंग, माधुरी गुप्ता, राजेश
कुमार, राजेश कोठियाल, दिनेश रावत,
राजपाल ठाकुर, देवदत्त शर्मा, दीपक बिष्ट,
राजू नरसिंह, पूनम डोभाल, मनोहरा,
सुमन रावत, रंकी राणा, पंकी धस्माना
आदि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय
नागरिक शिविर का लाभ लेने पहुंचे।

‘इन विभागों ने लगाए स्टॉल, पूर्व मंत्री ने किया निरीक्षण’

पूर्व मंत्री और विधायक डॉ
अग्रवाल ने नगर निगम ऋषिकेश के जन्म

व मृत्यु प्रमाण पत्र के स्टॉल, खाद्य पूर्ति विभाग के राशन कार्ड, राजस्व विभाग से स्थाई निवास तथा आय प्रमाण पत्र, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन के विद्युत सेवा शिफ्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिव्यांग व पेंशन प्रमाण पत्र, जलसंस्थान, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत निकुंज आजीविका स्वयं सहायता समूह, राधे आजीविका स्वयं सहायता समूह बनखंडी सहित अन्य विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया तथा जनता को सुविधा मिले इस दिशा में कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

÷ सर्वश्रेष्ठ कृषकों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित÷

तीन साल बेमिसाल कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री व क्षेत्र के विधायक डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने सर्वश्रेष्ठ कृषकों व उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों को भी सम्मानित किया।

नौलापानी से गुगड़ानी छीड़ा तक सड़क की मांग

चम्पावत (आएनएस)। ग्रामीणों ने नौलापानी -कठौल-फूलबाड़ी-गुगड़ानी छेड़ सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने इस संबंध में लोनिवि के ईई को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने वन विभाग की अनापत्ति के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने पर रोष जताया है। नौलापानी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने लोनिवि के ईई को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि सड़क के अभाव में ग्रामीणी पलायन कर रहे हैं। नौलापानी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ ही स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और मरीजों को सड़क तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।



कहा कि पूर्व में ग्रामीणों ने नाप भूमि से सड़क ले जाने की अनापत्ति भी दी है। इसके बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं होने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने

वालों में ग्राम पंचायत प्रशासक गीता देवी, ललित राम, प्रदीप प्रसाद, कुंदन सिंह, कलदीप, राम सिंह, मनोहर सिंह, जौहार

सिंह, महेश सिंह, अशोक सिंह, प्रयाग सिंह, चंचल सिंह, राधिका देवी, गजेन्द्र सिंह चौहान, उर्मिला चौहान, कीर्ति बल्लभ, देवकी देवी, शिवराज सिंह, नाथ सिंह, जीवन सिंह, जोगा राम, दीपक कुमार, देवीन राम, जगदीश राम, गोपाल राम, पुष्पा देवी, भवान राम, गणेश राम आदि ग्रामीण शामिल रहे।

शाहपुर-कल्याणपुर में बनेगा इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग

विकासनगर(आएनएस)। सहसपुर की शाहपुर-कल्याणपुर ग्राम पंचायत के बाशिंदों को बरसात के मौसम में कीचड़ से सनी सड़क पर आवागमन नहीं करना पड़ेगा। सोमवार को विधायक सहदेव पुंडेर ने पंचायत के मुख्य मार्गों को इंटरलॉकिंग टाइल्स मार्ग बनाने के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया। शाहपुर-कल्याणपुर पंचायत का मुख्य मार्ग बीते कई साल से सुधारीकरण की बात जोह रहा है। मार्ग पर एक दशक पूर्व बिछी पेंटिंग पूरी तरह से उखड़



चुकी है। डेढ़ किमी लंबे इस मार्ग पर सिर्फ गड्डों की भरमार है। बारिश होने पर गड्डों में पानी भर जाता है। इस बद्दहाल मार्ग पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। मार्ग का हाल देख ई-रिक्षा, ऑटो चालक भी यहां आने के लिए मना कर देते हैं, जिससे ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पैदल दूरी नापनी पड़ती है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए राज्य योजना के तहत मार्ग को इंटरलॉकिंग करने के लिए 33 लाख 27 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है।

देहरादून(आरएनएस)। पौड़ी के
पा विधायक राजकुमार पोरी का एक
म सोमवार को सोशल मीडिया पर

वायरल हो गया। इस बयान में विधायक पोरी कह रहे हैं कि अंग्रेज दो-चार साल और रहते तो पौड़ी का विकास हो जाता। बयान में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों में मसूरी के बाद पौड़ी का नंबर आता है। मैं समझता हूं कि अंग्रेज दो-चार साल और रहते तो पौड़ी का विकास हो जाता। उन्होंने कहा आजादी जल्दी मिल गई और अंग्रेज चले गए इस छूट गया। विधायक पोरी सोमवार को खूब वायरल हुआ।

बड़ी संख्या में लोगों के सोशल मीडिया में भी इसे शेयर किया गया। कई लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की और

भाजपा को घेरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने लिखा कि पौड़ी उत्तराखंड को सर्वाधिक सीएम देने वाला

**अंग्रेज दो चार साल
और रहते तो पौड़ी
का विकास हो जाता
: राजकुमार पोरी**

जिला है और जब पौड़ी के यह हाल हैं तो अन्य जिलों की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। उधर, विधायक पोरी से वायरल वीडियो के बाबत कई संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।



टीबी मुक्त पंचायतों के प्रधानों को प्रशस्ति पत्र दिए

नई टिहरी(आरएनएस)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हर घर को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर टीबी मुक्त पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। चिकित्साधिकारी ट्यूबरकुलोसिस डा. आशीष कुमार ने कहा कि टीबी एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन अगर समय पर इसका उपचार किया जाय तो वह ठीक हो जाती है। इसलिए सभी को इस संबंध में लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही उचित खान-पान पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कहा कि संपूर्ण भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान में सभी नागरिकों को अपना योगदान देना आवश्यक है। इस अवसर पर सुपरवाइजर महादेव प्रसाद, लैब असिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस अनिता खरोला आदि मौजूद रहे।



टीला और स्योली मल्ली को खिर्सू ब्लॉक में शामिल करने का विरोध

पौड़ी(आरएनएस)। थलीसैण ब्लॉक की ग्राम पंचायत टीला व स्योली मल्ली को खिर्सू ब्लॉक में शामिल किए जाने पर दोनों पंचायतों के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सोमवार को आयोजित बैठक में ग्रामीणों का कहना है कि वह थलीसैण ब्लॉक में ही रहना चाहते हैं लेकिन जिला प्रशासन व पंचायतीराज विभाग लगातार दोनों पंचायतों को खिर्सू ब्लॉक में शामिल किए जाने की कवायद कर रहा है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा ग्रामीणों की सहमति के खिलाफ पंचायतों को खिर्सू ब्लॉक में शामिल किए जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। थलीसैण ब्लॉक के ग्राम पंचायत टीला में आयोजित बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी पौड़ी जितेंद्र कुमार ने शिरकत ग्रामीणों से रायशुमारी की। इस मौके पर निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य टीला गणेश नेगी राठी, सामाजिक कार्यकर्ता मातवर नेगी, प्रशासक टीला मीना देवी, प्रशासक स्योली मल्ली देवेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान दिनेश सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत टीला व स्योली मल्ली के ग्रामीणों की सहमति के बिना उक्त पंचायतों को खिर्सू ब्लॉक में शामिल किए जाने का लगातार प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिसका प्रत्येक ग्रामीण पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने कहा कि दोनों पंचायतों के ग्रामीण थलीसैण ब्लॉक में ही रहना चाहते हैं। बावजूद इसके जन अपेक्षा के विपरीत प्रशासन-प्रशासन कवायद में जुटा है। उन्होंने बताया कि टीला व स्योली मल्ली के ग्रामीणों ने दोनों पंचायतों को थलीसैण में यथावत रखने का प्रस्ताव सौंपा है। इस अवसर पर ग्रामीण विक्रम सिंह, बेलम सिंह, भरत सिंह, कुंदन सिंह आदि मौजूद रहे। इधर, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार का कहना है कि थलीसैण ब्लॉक के ग्राम पंचायत टीला व स्योली को खिर्सू ब्लॉक में शामिल किए जाने को लेकर प्रस्ताव मिला था।



महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया

श्रीनगर गढ़वाल (आरएनएस)। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पौड़ी द्वारा सोमवार को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के श्रीनगर कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाली स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं समेत स्थानीय महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सब्सिडी, ऋण संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। साथ ही तैयार उत्पादों को आकर्षक व गुणवत्ता पूर्ण बनाने को लेकर सुझाव दिए गए। कार्यशाला में नगर क्षेत्र के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने प्रतिभाग कर रोजगार की दिशा में बेहतर कार्य करने के गुर सीखे। कार्यशाला में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डा. अल्का पांडे ने महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के

साथ अपने उत्पादों की मांग कैसे बढ़ाये इसे लेकर आवश्यक सुझाव दिए। कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ पैकेजिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी बाजार में तैयार किए गए उत्पादों की मांग बढ़ेगी। महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए आर्थिक समस्या के समाधान के लिए बैंक से लोन आवेदन करने, योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने संबंधित पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर आशीष पोखरियाल द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 15 से 35 फीसदी तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशाला में रेनु सुंदरियाल, कुसुम, लक्ष्मी, संगीता समेत अन्य महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। मौके पर केंद्र वस्त्रगार डीपी मैथानी, बी एल भारती, खुशी लाल आर्य, प्रीतम रावत, संजय आदि मौजूद रहे।

चारधाम यात्रा को देखते हुए 30 अप्रैल तक पूरे होंगे पैच वर्क

नई टिहरी(आरएनएस)। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर व चारधाम यात्रा के मद्देनजर विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों पर पैच वर्क व डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गये हैं कि विभिन्न विभागीय लंबित कार्यों को लक्ष्य बनाकर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विभागों में प्राप्त लंबित शिकायतों का निस्तारण कर शून्य करने को कहा गया है। इसी क्रम में ईई लोनिवि बौराड़ी ने बताया कि चारधाम के मद्देनजर जनपद में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिजिजनों द्वारा सड़कों पर पैच वर्क का कार्य किया जा रहा है। जाखणीधार-घनसाली मोटर मार्ग 4 किमी, सुलियाधार-वालकाखाल मोटर मार्ग 2 किमी, नटरज-भद्रकाली मोटर मार्ग 3 किमी, अगलाड-थल्यूड-अलमस मोटर मार्ग 5 किमी, कुल 14 किमी का पैच वर्क कार्य कर लिया गया है। इसके साथ ही लंबगांव- मोटना-रजाखेत-घनसाली मोटर मार्ग (एसएच-69) में 6 किमी नवीनीकरण का कार्य कर लिया गया है।

टीएचडीसी की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को दें प्राथमिकता



नई टिहरी(आरएनएस)। जिले भर के बेरोजगार युवाओं ने निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हितेश चौहान के नेतृत्व में सोमवार को डीएम मयूर दीक्षित और पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत से मिलकर जिले में रोजगार देने की मांग की है। कहा कि टीएचडीसी इंडिया के अंतर्गत डैम क्षेत्र में बालाजी, नेटकॉन

आदि कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। सोमवार को बेरोजगार युवाओं ने पहले पालिकाध्यक्ष मोहन सिंह रावत से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। कहा कि टिहरी जिले में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, विभागों में स्थानीय युवाओं की

उपेक्षा की जा रही है। इस पर पालिकाध्यक्ष ने अपने स्तर से प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मिलकर बताया कि टीएचडीसी के अधीन कई कंपनियां पीएसपी और अन्य कार्य में लगी हैं लेकिन इसमें भी स्थानीय युवाओं को वरीयता नहीं दी जा रही है।

तीन साल में राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल कीं: दिलीप

पौड़ी(आरएनएस)। थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय पटोटिया नैनीडांडा में सोमवार को मुख्य अतिथि विधायक दिलीप रावत ने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में उत्तराखंड सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में अनेक विकास योजनाएं चलाई गई हैं। गांव-गांव सड़क पहुंचाने व कच्ची सड़कों का सुधारीकरण, डामरीकरण कार्य तेज गति से चल रहा है। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में महिला समूहों, महिला मंगल दलों ने भागीदारी की। महिला मंगल दल भौन, नौणियाखेत आदि ने पारंपरिक लोकगीतों, थड्या गीतों आदि की सुंदर प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन पहली बार राज्य में हुआ। हमारा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र



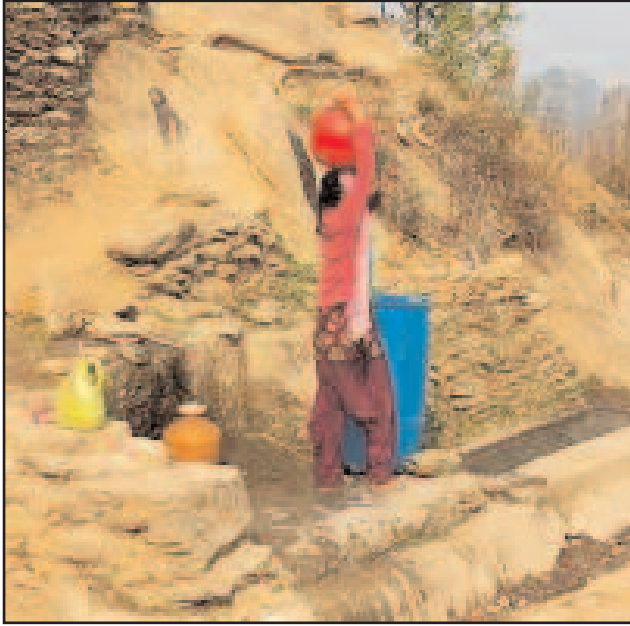
की बेटी अंकिता ध्यानी ने राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। विधायक दिलीप रावत ने सुदूर गांवों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनका समाधान किया। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान हेतु उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए। कहा कि अफसरों, कर्मचारियों की लापरवाही और काम में हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्यक्रम में सीडीओ गिरिश गुणवंत, एसडीएम शालिनी मौर्य, बीडीओ प्रमोद कुमार पांडेय, ब्लॉक प्रमुख प्रशांत कुमार, ज्येष्ठ उप प्रमुख ललित पटवाल, कनिष्ठ उप प्रमुख रेखा देवी, दीपक भंडारी, नीरज पंत, सुरेंद्र प्रताप, मुन्नी ध्यानी, प्रकीर्ण नेगी, मनोज खर्कवाल, सत्यपाल सिंह, देवेन्द्र रावत, जंग बहादुर नेगी, अर्जुन पटवाल, सुरेंद्र प्रताप आदि मौजूद रहे।



कुमाऊं क्षेत्र में जल गुणवत्ता निगरानी पर कार्यशाला का आयोजन

अल्मोड़ा (आरएनएस)। उत्तराखंड सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने और अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर मानसखंड विज्ञान केंद्र, अल्मोड़ा में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय 'उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के लिए जल गुणवत्ता निगरानी और व्यावहारिक प्रशिक्षण' था, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और गुणवत्ता सुधार पर जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के शुभारम्भ पर केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और प्रभारी डॉ. नवीन चंद्र जोशी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यशाला की रूपरेखा और विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। मुख्य संयोजक डॉ. जी. सी. एस. नेगी ने 'उत्तराखंड में जल गुणवत्ता के मुद्दों का अवलोकन' विषय पर व्याख्यान देते हुए प्रदेश में



जल गुणवत्ता से जुड़े शोध और प्रयासों को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता प्रो.

जे. एस. रावत ने 'प्रदूषण मुक्त जल के लिए झरनों, नौलों और नदियों के

पुनर्भरण क्षेत्रों का संरक्षण' पर व्याख्यान दिया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रो. एन. एस. भंडारी ने 'जल-जीवन का योगिक' विषय पर व्याख्यान देते हुए जल की उपयोगिता और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य प्रशिक्षक डॉ. महादेव सेमवाल, निदेशक, ईकॉन प्रयोगशाला एवं परामर्श, देहरादून ने भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक मापदंडों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला का संचालन प्रदीप तिवारी ने किया। कार्यशाला में एसएसजे विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के वानिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विभागों के 150 से अधिक छात्रों, शोधार्थियों और प्राध्यापकों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम में विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विकास खंड स्याल्दे में जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित

अल्मोड़ा (आरएनएस)। वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकासखंड स्याल्दे में जन सेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन तहसील परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर



विधायक सल्ट महेश जीना द्वारा शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में सरकार की समस्त विभागों से सम्बंधित योजनाओं एवं पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सम्मुख रखा गया। शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों एवं विभागों के कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक महेश जीना ने उत्तराखंड सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों एवं सल्ट

विधानसभा में हुए विकास कार्यों को समस्त जनता के सम्मुख रखा। शिविर में विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गये एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की बिक्री की गयी। इस दौरान श्रम बोर्ड के सदस्य सुरेश

कड़कोटी एसडीएम भिकियासैण सीमा विश्वकर्मा, खंड विकास अधिकारी स्याल्दे शैलेन्द्र जोशी, खंड शिक्षा अधिकारी वन्दना रौतेला सहित कृषि, उद्यान, समाज कल्याण, बाल विकास, श्रम, जिला पूर्ति, ग्राम्य विकास, एवं पंचायती राज, मत्स्य, जल संस्थान, आयुर्वेदिक एलोपैथिक, होम्योपैथिक आदि समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं जनता उपस्थित रहे।

जनसेवा थीम पर बहुउद्देशीय, चिकित्सा शिविर होंगे आयोजित

अल्मोड़ा (आरएनएस)। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के निर्देशों के क्रम में सरकार के 03 वर्ष पूर्ण होने के



अवसर पर जनसेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविरों/चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को विकासखण्ड भिकियासैण के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज भिकियासैण में, 26 मार्च को विकासखण्ड हवालबाग के विकासखण्ड सभागार में,

विकासखण्ड चौखुटिया के बाखली मैदान में, विकासखण्ड सल्ट के राजकीय इंटर कालेज खुमाड़ में, विकासखण्ड धौलादेवी के गांधी इंटर कालेज पनुवानौला में, 27 मार्च को विकासखण्ड शिवपुरी के रामलीला मैदान धौलछीना में, विकासखण्ड द्वाराहाट के श्री शीतला पुष्कर रामलीला मैदान द्वाराहाट में, 28 मार्च को विकासखण्ड लमगाड़ा के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कालेज लमगाड़ा में, 29 मार्च को विकासखण्ड ताकुला के

सोमनाथ ग्राउंड सोमेश्वर में आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि वे सम्पूर्ण तैयारी के साथ विभागीय योजनाओं की जानकारी से सम्बन्धित अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित विभागीय स्टॉल अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

मजबूर युवती से देह व्यापार कराने पर दो आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज

रुद्रपुर (आरएनएस)। रोजगार के लिए भटक रही युवती की मजबूरी का फायदा उठाकर दो महिलाओं ने उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया। पेशान होकर युवती ने पुलिस को तहरीर देकर दोनों महिलाओं पर शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिला नैनीताल की एक बीस वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि उसके बचपन में ही माता-पिता का स्वर्गवास हो गया था। वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी। दो वर्ष पूर्व वह नौकरी तलाश में रिश्तेदारों का घर छोड़कर किच्छा आ गई। यहां उसकी मुलाकात रेलवे फाटक पर छाया पत्नी संजय सैनिक कॉलोनी निवासी बंडिया से हुई। छाया ने युवती को नौकरी दिलाने का भरोसा देते हुए अपने घर में रख लिया। आरोप है कि युवती की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे देह व्यापार में धकेल दिया और अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर देह व्यापार कराने लगी।

कांग्रेस ने गिनाई धामी सरकार की तीन साल की नाकामियां

रुद्रपुर (आरएनएस)। कांग्रेस ने धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर उसे पूरी तरह विफल करार देते हुए कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में सिर्फ भाजपा नेताओं का विकास हो रहा है, जबकि आम जनता, किसान, व्यापारी और बेरोजगार खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि धामी सरकार तीन साल के कार्यकाल की झूठी वाहवाही लूटने के लिए करोड़ों रुपये प्रचार में बहा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। महिलाओं और दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है। पुलिस प्रशासन भाजपा नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है। खनन और आबकारी घोटाले चरम पर हैं। महिला कांग्रेस

प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि सरकार 'सेवा दिवस' के नाम पर जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई को लुटाने में लगी है। उन्होंने आरोप



लगाया कि राज्य भ्रष्टाचार का मॉडल बन चुका है और अब रिश्तखोरी गूगल पे और पेटीएम के जरिए हो रही है। खनन और शराब माफिया को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने सरकार पर किसानों और व्यापारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी

करने का वादा किया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। शराब सस्ती कर दी गई है, लेकिन डीजल, बिजली और खाद के दाम आसमान छू रहे हैं। हाईवे निर्माण के चलते सैकड़ों छोटे व्यापारियों को उजाड़ दिया गया और पुनर्वास के नाम पर लाखों रुपये मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सरकार की नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और 2027 के चुनाव में बदलाव के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा सरकार के झूठे वादों और खोखली घोषणाओं से गुमराह नहीं होगी। प्रेसवार्ता में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा, अनिल शर्मा, महानगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस मोनिका ढाली, ममता रानी पूर्व मेयर प्रत्याशी, सतीश राजपूत, निसार खान मौजूद रहे।

एनयूजे की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी का अल्मोड़ा में स्वागत

अल्मोड़ा (आरएनएस)। नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (एनयूजे) उत्तराखंड की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी के अभिनंदन समारोह का आयोजन अल्मोड़ा जनपद इकाई द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं संरक्षक त्रिलोक चंद्र भट्ट ने की। इस अवसर पर नव-निर्वाचित प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। बैठक में प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव गोपाल दत्त गुररानी ने किया। उन्होंने संगठन में नए पत्रकारों को जोड़ने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर

जोर दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन पत्रकारों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, न्यूज इमरजेंसी रिलीफ फंड, मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन तथा उत्तर पद हिंदी मासिक पत्रिका की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रदेश अध्यक्ष दया जोशी ने पत्रकारों के हित में किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संगठन में अनुशासन बनाए रखने और स्वच्छ छवि वाले पत्रकारों को जोड़ने की बात कही। उन्होंने त्रैमासिक बैठकों के आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों के उत्सव, निशुल्क मेडिकल कैंप और दिव्यांग प्रतिभाओं के लिए



विशेष कार्यक्रम चलाने पर बल दिया। अल्मोड़ा इकाई के जिला अध्यक्ष दरबान सिंह ने संगठन को सुदृढ़ करने और दूरस्थ क्षेत्रों में बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी में सचिव एवं उपाध्यक्ष पद रिक्त हैं, जिन्हें शीघ्र ही भरा जाएगा।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दया जोशी, महासचिव गोपाल दत्त गुररानी, संगठन मंत्री कैलाश चंद्र भट्ट, प्रदेश सचिव पुष्पेश राणा, स्वराज पाल, कंचना तिवारी, देवेन्द्र बिष्ट, हरीश त्रिपाठी, विनोद जोशी, शिवदत्त पांडे, गणेश रावत और मोहित अधिकारी सहित कई पत्रकारों ने अपने विचार साझा किए।

संपादकीय

विश्व की मदद करने वाला भारत है अब

नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के दायित्व की शपथ ग्रहण कर रहे थे, जिसको लेकर देश में हर्ष का वातावरण था, साथ ही विश्व भर का शीर्ष नेतृत्व भारत की ओर देख रहा था, इस हर्ष और उल्लस के वातावरण में जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें नौ तीर्थ यात्री मारे गये थे एवं 41 तीर्थ यात्री घायल हुये थे, इस आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल की भूमिका थी। आतंकी जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल को पिछले शनिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके अगले ही दिन क्रेटा में आतंकी अब्दुल बाकी नूरजई को मारने की खबर आ गई, इससे पहले भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा आतंकीयों को जहनुम भेजा जाता रहा है, जिससे आतंकीयों और आईएसआई में दहशत का माहौल बन गया है। डरी-सहमी आईएसआई आतंकीयों को सुरक्षा मुहैया करा रही है, वहीं भारत अपने सुरक्षा तंत्र को वैश्विक स्तर का बना रहा है, इस सब पर ही चर्चा कर रहे हैं बोपी गौतम... पाकिस्तान में हाफिज सईद के करीबी और कश्मीर में कई हमलों में संलिप्त रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल की पिछले शनिवार की रात में 15 मार्च 2025 को हत्या कर दी गई। झेलम जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का शीर्ष कमांडर जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों के लिये वांछित था। जिया-उर-रहमान का जन्म 4 फरवरी 1982 को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सांगहर जिले में हुआ था। 2000 के दशक के आस-पास उसने लश्कर-ए-तैयबा के लिये जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की थी, वह 26/11 मुंबई हमले के मास्टर माइंड और लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का सर्वाधिक विश्वसनीय साथी बताया जाता था। जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल ने लश्कर-ए-तैयबा में अहम भूमिका निभाई थी, उसने कई आतंकी हमलों का षड्यंत्र रचा था, वह पुंछ और रजौरी क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, वह भारत में कई बड़े आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिये जिम्मेदार था, जिनमें 2023 में रजौरी जिले के गांव दंगरी में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला भी सम्मिलित था, इस हमले में पांच लोग मारे गये थे। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में 2024 में बस पर हमला हुआ था, जिसमें वैष्णो देवी से लौट रहे नौ तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 41 लोग घायल हुये थे। 2023 में भट्ट-दुरियां और कंडी हमले में भारतीय सेना के जवान का बलिदान हुआ था, जिसमें जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल की ही भूमिका मानी जाती है। जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल पाकिस्तान के कोटली जिले में लश्कर के एक छोटे आतंकवादी समूह खुदरझा डिट्स का प्रभारी था, वह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लश्कर के आतंकवादियों और उसके ऑपरेटरों के बीच की मुख्य कड़ी बन गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल को कई आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित पाया था और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के अंतर्गत आरोपित किया था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच में उसकी भूमिका सामने आई थी, इसीलिये वह भारत में वांछित आतंकवादियों की सूची में सम्मिलित था।

संदेह के घरे में न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली



अभय कुमार
(प्रधान संपादक)

याचिका में दावा किया गया है कि जजों को अलग दर्जा दे देने के चलते कुछ मौकों पर पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में भी वह एफआईआर से बच गए हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में नकदी के वीडियो वायरल होने के बाद न्यायपालिका के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया जाने लगा है। यह मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को उन्हें तत्काल स्थानांतरित करने का फैसला लेना पड़ा। साथ ही फिलहाल उन्हें न्यायिक कार्य से भी अलग कर दिया गया है। इस मामले में मुंबई के वकीलों ने भी एक याचिका लगाई है। इस याचिका में कहा गया है कि जज के घर पर बड़ी मात्रा में पैसा मिलना एक आपराधिक मामला है। इसके लिए तीन जजों की जांच कमेटी बनाने की बजाय पुलिस समेत दूसरी एजेंसियों को जांच के लिए कहना चाहिए।

याचिका में यह कहा गया है कि 14 मार्च को जज के घर में जली हुई नकदी मिलने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जजों की जांच कमेटी को मामला सौंप दिया गया है, जो कि सही नहीं है। जिस तरह आम नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होती है, वैसा ही इस मामले में भी होना चाहिए था। याचिका में दावा किया गया है कि जजों को अलग दर्जा दे देने के चलते कुछ मौकों पर पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में भी वह एफआईआर से बच गए हैं। नेशनल लॉयर्स कैपेन फॉर जूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म नाम की संस्था से जुड़े इन याचिकाकर्ताओं ने याद दिलाया है कि जजों के भ्रष्टाचार और दूसरे गलत आचरण की जांच के लिए 2010 में संसद में जूडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटैबिलिटी बिल लाया गया था, लेकिन वह कानून नहीं बन सका। उल्लेखनीय है कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। जज के निजी सचिव ने पीसीआर को बुलाया। इसके बाद आग पर तो काबू पा लिया गया लेकिन इस दौरान पुलिस और दमकल कर्मियों को बंगले के अंदर एक कमरे में कई बोरियों में बड़ी मात्रा में नोटों का ढेर दिखा। यह ढेर आधा जलकर खाक हो गया था। यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में एक्शन

लेते हुए फौरन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई जिसमें जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी। अब तक जांच में जो कुछ सामने आया है, वह सब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया है। इसमें नोटों के ढेर की अधजली तस्वीर भी शामिल है। 14 मार्च की रात जज के निजी सचिव ने आग लगने की सूचना दी थी।



फायर ब्रिगेड को अलग से कॉल नहीं किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 15 मार्च की सुबह मामले की जानकारी दी। पुलिस कमिश्नर ने अधजले कैंस की तस्वीरें और वीडियो भी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को भेजीं। कमिश्नर ने बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह भी बताया कि जज के बंगले के एक सिविलरिटी गार्ड ने उन्हें बताया कि 15 मार्च को कमरे से मलबा साफ किया गया है। इसके बाद मामले को दबाने झुटलाने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी फायर सर्विस के एक अधिकारी के बयान से कोई नकदी नहीं मिलने की बात कही गई तो कभी जज साहब का स्थानांतरण नियमित प्रक्रिया में होने के बयान आए। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में जज साहब के घर की आग में अधजले नोटों के बोरो की तस्वीर वायरल हो गई और अंततः जिम्मेदार बड़ी अदालत को इस सबको लेकर अपना नजरिया साफ करना पड़ा। इस मामले में जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा से मुलाकात की तो जस्टिस

है कि वह अपने फोन को डिपोज न करें, न ही चैट मिटाएं।

इस घटनाक्रम में संविधान के अनुसार, किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता या कदाचार के आरोपों की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन-हाउस प्रक्रिया तैयार की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत, सीजेआई पहले संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। यदि जवाब संतोषजनक नहीं होता या मामले में गहन जांच की जरूरत महसूस होती है, तो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की एक इन-हाउस जांच समिति गठित कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल केवल वर्मा के ट्रांसफर का फैसला लिया गया है, उनका निर्रबन नहीं हुआ है। जांच के बाद जज वर्मा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कुछ जज इस मामले में सिर्फ तबादले की कार्रवाई को ठीक न मानते हुए न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

बांग्लादेश के बदलते सुरों को गंभीरता से लेना होगा

-ललित गर्ग-

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनस ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं। बस कुछ गलतफहमियां हैं, जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली स्थिति में यूनस किन रिश्तों के मजबूत होने की बात कर रहे हैं, कैसी गलतफहमियां और किनके द्वारा उत्पन्न गलतफहमियों की बात वे कर रहे हैं? यूनस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने भारत से दूरियां बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां हिन्दुओं एवं हिन्दू मन्दिरों पर कहर बरपाया गया, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कवायद करते हुए भारत को डगने की कोशिशें हुईं, कट्टरपंथी एवं जिहादी ताकतों को सहयोग, समर्थन और संरक्षण दिया गया है, इन सब स्थितियों को उग्र से उग्रतर बनाकर अब यूनस किन रिश्तों की बात कर रहे हैं, वे क्यों बैंकांक में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं? बांग्लादेश का



भारत-विरोधी रवैया दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि विडम्बनापूर्ण बना है। भारत से पंगा बांग्लादेश को कितना महंगा पड़ रहा है, इसका अनुमान बांग्लादेश की बिगड़ती अर्थ-व्यवस्था, शांति-व्यवस्था एवं अराजकता को देखते हुए सहज ही लगाया जा सकता है। इन ज्वलंत होती स्थितियों का सबसे बड़ा कारण भारत से दुश्मनी ही है। बांग्लादेश में

अराजकता, हिंसा एवं जर्जर होते हालात को मोहम्मद यूनस सरकार निर्यंत्रित नहीं कर पा रही हैं। मुल्क अभी भी भीड़ की हिंसा की उन घटनाओं से उबर नहीं रहा है, जो पिछले अगस्त में शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन के बाद शुरू हुई थी। यूनस से क्षेत्र में शांति व सद्भाव की जो उम्मीदें थी, उसमें उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ को आगे

करके निराश ही किया है। उनकी सरकार लगातार विघटनकारी, अडिगल व बदमिजाजी का रुख अपनाए हुए है। यदि भारतीय प्रधानमंत्री बैंकांक में यूनस से वार्तालाप करते हैं तो उन्हें उनके इरादों को लेकर सतर्क एवं सावधान रहना चाहिए।

भारत प्रारंभ से बांग्लादेश का सहयोगी एवं हितैषी रहा है, इसी कारण उसने पिछले डेढ़ दशकों में जो आर्थिक तरक्की हासिल की, छह फीसदी से अधिक दर से जीडीपी को बढ़ाया और 2026 तक विकासशील देशों के समूह में शामिल होने का सपना देखा, उन सब पर मोहम्मद यूनस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के संकीर्णतावादी एवं दुराग्रही सोच के कारण काली छाया मंडराने लगी है। बांग्लादेश में भारत विरोधी वातावरण तैयार किया जा गया, वहां हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं पर भारत की तमाम चिंताओं के बावजूद गंभीरता नहीं दिखाई गयी और अल्पसंख्यक हिन्दुओं के दमन को रोकने के लिए वांछित कदम उठाने से इनकार किया गया है।

सवालोंने भरा फैसला, जज यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट करने की सिफारिश कई सवालोंने को जन्म देने वाली है। इसलिए और भी अधिक, क्योंकि जब जस्टिस वर्मा के घर लगी आग बुझाने के दौरान उनके यहां बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने और इस कारण उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की खबर आई थी तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इस तबादले का नकदी कांड से कोई लेना-देना नहीं। फिर उसकी ओर से कहा गया कि उनका तबादला रोका जा रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। अब उनके तबादले की सिफारिश कर दी गई और वह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कठोर आपत्ति के बावजूद। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित कर दी है, लेकिन आखिर यह जांच शुरू होने के पहले उनके तबादले का क्या औचित्य? प्रश्न यह भी है कि यदि जस्टिस यशवंत वर्मा जैसा मामला किसी नेता, नौकरशाह, कारोबारी अथवा अन्य किसी का होता तो क्या उसके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार होता? व तब तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता और सीबीआई, ईडी आदि भी सक्रिय हो गई होती। आखिर एक जैसे

मामलों में दो तरह का आचरण क्यों? क्या यह विचित्र नहीं कि जस्टिस वर्मा के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? क्या इसकी जरूरत इसलिए नहीं समझी गई कि मामला हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है? आखिर आम जनता को ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने से कैसे रोका जा सकता है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अलग नियम हैं और शेष अन्य के लिए अलग? यह सही है कि उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीश विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि उनके संदर्भ में नियम-कानून भी विशिष्ट हों। यह दोहरापन तो लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी मामले में न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। न्यायाधीशों के मामले में तो ऐसा और भी होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के प्रति आम आदमी के भरोसे का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए कि यह भरोसा ढिग रहा है। यह ठीक नहीं कि जब इस भरोसे को बहाल करने की जरूरत है, तब ऐसे काम हो रहे हैं, जो संदेह भरे सवाल खड़ा करने वाले हैं। इससे इन्कार नहीं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता की कीमत पर नहीं।

90 लाख करदाताओं ने फाइल किया अपडेटेड आईटीआर, सरकार को मिला 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व

नई दिल्ली। हाल ही में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में 90 लाख से अधिक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। यह सरकार द्वारा शुरू की गई वॉलंटरी कंप्लायंस स्कीम (वीसीएस) की सफलता को दर्शाता है। सरकार ने 2022 में स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की योजना के तहत अतिरिक्त आयकर का भुगतान करदाताओं के लिए किसी स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर से दो साल तक अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) फाइल करने का विकल्प पेश किया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कुल मिलाकर, असेसमेंट ईयर 2021-22 से असेसमेंट ईयर 2024-25 के बीच 9.176 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू फाइल किए गए, जिससे सरकार को 9,118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ।

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि करंट



असेसमेंट ईयर (2024-25) में 28 फरवरी तक करीब 464,000 अपडेटेड

आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431.20 करोड़ रुपये का कर चुकाया

गया है। सरकार ने फाइनेंस बिल, 2025

के जरिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को संबंधित असेसमेंट ईयर से चार साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। योजना की सफलता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2.979 मिलियन से अधिक आईटीआर-यू दाखिल किए गए और 2,947 करोड़ रुपये अतिरिक्त कर चुकाए गए। असेसमेंट ईयर 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 4.007 मिलियन और 1.724 मिलियन अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए और अतिरिक्त 3,940 करोड़ रुपये और 1,799.76 करोड़ रुपये कर चुकाए गए। एक दूसरे सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी - पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दे दी है। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और छोटे व्यापारियों को यूपीआई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के लक्ष्य के अनुरूप उठाए गए हैं। डिजिटल

भुगतान को बढ़ावा देना वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। ग्राहकों/व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान उद्योग द्वारा किए गए व्यय को मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के जरिए वसूला जाता है।

मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट एक शुल्क है जिसे व्यापारियों और अन्य व्यवसायों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को देना होगा। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एमडीआर आमतौर पर लेनदेन राशि के प्रतिशत के रूप में आता है। आरबीआई के अनुसार, डेबिट कार्ड के लिए सभी कार्ड नेटवर्क पर लेनदेन मूल्य का 0.90 प्रतिशत तक का एमडीआर लागू है। एनपीसीआई के अनुसार, यूपीआई पी2एम (पर्सन टू मर्चेन्ट) लेनदेन के लिए 0.30 प्रतिशत तक का एमडीआर लागू है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2020 से रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन के लिए एमडीआर शून्य कर दिया गया है।

सर्पा बाजार में सस्ता हुआ सोना, चांदी में बदलाव नहीं

नई दिल्ली। घरेलू सर्पा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट का रुख नजर आ रहा है। आज की कमजोरी के कारण देश के ज्यादातर सर्पा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 89,610 रुपये से लेकर 89,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 82,140 रुपये से लेकर 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। ये चमकीली धातु आज भी दिल्ली सर्पा बाजार में 1,00,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही कारोबार कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 89,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 89,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 82,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 89,660 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 82,190 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना

आज 89,610 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 82,140 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 89,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 82,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्पा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 89,760 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। वहीं पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 89,660 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 82,190 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 89,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्पा बाजार में भी आज सोना सस्ता हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 89,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्पा बाजारों में 22 कैरेट सोना 82,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख बना हुआ है। आज के कारोबार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही मुनाफा वसूली के चक्र में हुई बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में कुछ देर के लिए गिरावट भी आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आ गई। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.92 प्रतिशत और निफ्टी 0.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजी, बजाज फिनसर्व, इंफोसिस और टीसीएस के शेयर 2.76 प्रतिशत से लेकर 1.92 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेट्रीज, इंडसइंड बैंक, श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो के शेयर 2.54 प्रतिशत से लेकर 0.86 प्रतिशत की

गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,435 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग



हो रही थी। इनमें से 1,175 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,260 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 26 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 4 शेयर

बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 36 शेयर हरे

निशान में और 14 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे। बीएसई का सेंसेक्स आज 311.90 अंक उछल कर 78,296.28 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार में बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में यह सूचकांक गिर कर

78,085.53 अंक के स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट के बाद खरीदारों ने मोर्चा संभाला और चौतरफा लिवाली शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 719.59 अंक की तेजी के साथ 78,703.97 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 93.15 अंक की तेजी के साथ 23,751.50 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण पहले 10 मिनट के कारोबार में ही यह सूचकांक गिर कर 23,664.90 अंक तक पहुंच गया। हालांकि इस गिरावट के बाद तेजियों ने जोर बना दिया, जिससे इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई। बाजार में लगातार जारी लिवाली और बिकवाली के बीच सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद निफ्टी 196.60 अंक की तेजी के साथ 23,854.95 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजारों में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ पॉलिसी को लेकर नरमी का संकेत दिए जाने के कारण अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान जबरदस्त उत्साह का माहौल बना रहा, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए। डाउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 600 अंक से अधिक की मजबूती हासिल करने में

सफल रहा। इसी तरह एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 100.01 अंक यानी 1.76 प्रतिशत उछल कर 5,767.57 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसी तरह नैस्डैक 404.54 अंक यानी 2.27 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,188.59 अंक के स्तर पर बंद हुआ। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 42,557.26 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,638.01 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,022.33 अंक के स्तर



पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.17 प्रतिशत टूट कर 22,852.66 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों में आज मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के 9 बाजारों में से 5 के सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 4 सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। हंगे सेंग इंडेक्स में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 538.24 अंक यानी 2.25 प्रतिशत टूट कर 23,367.32 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसके अलावा कोस्पी इंडेक्स से 0.34 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,623.16 अंक के स्तर पर, सेट कपोजिट इंडेक्स 0.35 प्रतिशत फिसल

कर 1,185.84 अंक के स्तर पर और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,364.05 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.40 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,790 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह निकोई इंडेक्स 180.89 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 37,789.38 अंक के स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा ताइवान वेटेड इंडेक्स 171.82 अंक यानी 0.78 प्रतिशत उछल कर 22,278.46 अंक के स्तर पर, स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.89 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,971.49 अंक के स्तर पर और जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 6,203.97 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।



मानना है कि खादू श्याम बाबा हर भक्त की सुनते हैं और इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यात्रा के दौरान संत केदार ने एक मोटरसाइकिल को रथ में बदल रखा है, जिसमें खादू श्याम की अखंड ज्योति जल रही है। वे इसी रथ में ढहरते हैं और रात भी यहीं बिताते हैं। जब दिनभर की दंडवत यात्रा पूरी हो जाती है, तब वे मोटरसाइकिल में ही विश्राम करते हैं। संत के इस कठिन संकल्प को पूरा करने में खादू श्याम के श्रद्धालु लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। भरतपुर से लेकर खादू श्याम तक भक्त उन्हें भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजें मुहैया करा रहे हैं। अन्य श्रद्धालु भी इस पुण्य कार्य में सहयोग कर सकते हैं। सात साल की यह कठिन यात्रा न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति संत केदार कटारा की अटूट आस्था और समर्पण को भी दर्शाती है।

डीके शिवकुमार के बयान पर कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए: प्रह्लाद जोशी

नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के 'संविधान बदल रहा है' बयान पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने डीके शिवकुमार के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली में संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार द्वारा संविधान को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और डीके शिवकुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। इनका छिपा हुआ एजेंडा इन्होंने सार्वजनिक कर दिया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबासाहेब अंबेडकर का अपमान किया

है और बहुत बार संविधान में संशोधन किया। कांग्रेस ने बार-बार संविधान का भी अपमान किया है। डीके शिवकुमार के बयान पर कांग्रेस को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।

दरअसल, डीके शिवकुमार से हाल ही में एक न्यूज चैनल के मंच पर कर्नाटक सरकार की मुस्लिम आरक्षण नीति को कोर्ट में चुनौती दिए जाने को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा था, "देखते हैं, कोर्ट क्या कहता है, हमने कुछ शुरू किया है। मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे। हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है, और ऐसे फैसले हैं जो संविधान



को बदल देते हैं। उनके इस बयान के बाद सोमवार को बेंगलुरु की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीके शिवकुमार का पुतला फूँका था। वहीं, राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजजू ने इस मुद्दे को उठाया था। भाजपा के कई नेताओं ने भी उनके बयान की आलोचना करते हुए उनसे माफ़ी मांगने की मांग की।

हालांकि, डीके शिवकुमार ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि भाजपा ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर भाजपा की आपत्ति पर

मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा बेवजह के आरोप लगाती है। डीके शिवकुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, अगर कहा भी है तो बहुत ही हल्के अंदाज में। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम इसे भी करेंगे। संविधान में संशोधन हुए हैं। लेकिन, इस देश में किसी को भी डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, वे पहले ही 400 से 240 पर आ गए हैं और उन्हें 240 से 100 पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

सांसद राशिद इंजीनियर की कस्टडी पैरोल याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा, 'अधिकारों का होगा क्या?'

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामुला से सांसद राशिद इंजीनियर की कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राशिद इंजीनियर ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए याचिका डाली थी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसे लेकर लोकसभा के महासचिव से याचना की जा सकती है।

एनआईए ने राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संसद सत्र में शामिल होना किसी सांसद का संवैधानिक अधिकार नहीं है। राशिद पर गंभीर आरोप हैं, और यदि वह संसद में कुछ कहते हैं, तो उसकी गंभीरता क्या होगी? दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि राशिद यदि कोई राजनीतिक बयान देते हैं, तो उससे समस्या हो सकती है और इस तरह के आरोपियों के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए। राशिद इंजीनियर के वकील ने कहा, "उन्होंने संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की



मांग की है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दिया था।

वकील ने एनआईए द्वारा उठाई गई आपत्तियों को पहले से उठाए गए मुद्दे बताया और कहा कि मामले में अभी

तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि राशिद इंजीनियर ने चुनाव लड़ा और जीता, शपथ के लिए संसद गए और संसद सत्र में शामिल हुए। अब दुबारा संसद सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट के सामने हैं। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि अगर वह दस साल तक जेल में रहे और दस साल तक सांसद भी रहे, तो उनके अधिकारों का क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राशिद इंजीनियर के भागने का कोई खतरा है? कोर्ट ने कहा कि वे उन्हें सेलफोन के उपयोग से रोक सकते हैं, लेकिन संसद में उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। संसद में जो कुछ होता है, उसका ध्यान लोकसभा अध्यक्ष और सभापति रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम उस तथ्य को नजरअंदाज कर दें कि वह निर्वाचित सांसद हैं? राशिद लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद में हैं और लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और स्थिति को कमतर नहीं आंकना चाहिए।

एक व्यक्ति हत्या पर एनएचआरसी लिया संज्ञान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने (एनएचआरसी) ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में अपनी जान को खतरा होने की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता के कारण एक व्यक्ति की कथित हत्या का स्वतः संज्ञान लिया। कथित तौर पर पीड़ित क्षेत्र में वक्फ भूमि के खिलाफ कानूनी मामलों में सक्रिय रूप से शामिल था। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और तिरुनेलवेली के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में चार व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दिनदहाड़े एक सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या कर दी गई। कथित तौर पर पीड़ित एक कार्यकर्ता था जो क्षेत्र में वक्फ भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी मामलों की लड़ाई लड़ रहा था और उसे कुछ लोगों से मौत की धमकियाँ मिल

रही थीं। उसने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी क्योंकि वह उनके साथ मिली हुई थी। आयोग ने पाया है कि



समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो पीड़ित के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करती है। इसलिए, इसने पुलिस महानिदेशक और जिला कलेक्टर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाई

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को विभिन्न दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले पर चर्चा की मांग करने वाले कुछ सांसदों की अपील पर सदन को क्या कदम उठाना चाहिए। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति धनखड़ ने बताया कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के तहत, नियत कामकाज स्थगित कर चर्चा करने के लिए आठ नोटिस मिले हैं जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया है। इनमें एक नोटिस आईयूपएमएल के हारिस बीरन का भी था। सभापति ने बताया कि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक मंगलवार को शाम साढ़े चार बजे बुलाई है। धनखड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को सदन के नेता जे पी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से "बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुलाकात की थी।" उन्होंने कहा, "यह मुद्दा निस्संदेह काफी गंभीर है।" उनके अनुसार,

खरगे ने सदन के नेताओं की बैठक बुलाने का सुझाव दिया था और नड्डा ने इस पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा, "हम तीनों ने घटनाक्रम पर गौर किया और यह भी देखा कि पहली बार, अभूतपूर्व तरीके से, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने सब कुछ सार्वजनिक मंच पर डालने की पहल की।" धनखड़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने से संबंधित फोटो, वीडियो सहित जांच रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की ओर प्रोत्साहन दे रहे थे। दिल्ली के पंथ लुटियंस इलाके में 14 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के एक कमरे में आग लगने के बाद, उसे बुझाते समय अग्निशमन कर्मियों और पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से नकदी बरामद की थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आग की घटना के बाद नोटों की "चार से पांच अथजली बोरियां" जाए जाने की जांच के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है।

कांग्रेस ने सरकार पर वित्त विधेयक के जरिए पेंशनभोगियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर वित्त विधेयक, 2025 में पेंशनभोगियों को प्रभावित करने वाले प्रावधान लाने का और राज्यों पर आर्थिक 'ब्लैकमेल' कर नियंत्रण के प्रयास का आरोप लगाया, वहीं भाजपा ने कहा कि सरकार ने संघीय ढांचे के तहत पिछले दस वर्ष में अवसंरचना पर पूंजी व्यय काफी बढ़ाया है।

लोकसभा में वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर इस विधेयक में 'गुप्त एजेंडा' रखने और इसके रास्ते पेंशन कानून में संशोधन करके पेंशनभोगियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए बड़े कदम उठाने का दावा करने वाली सरकार पेंशनभोगियों पर हमला क्यों कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा, "पेंशनभोगियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या वित्त मंत्री विधेयक में इससे संबंधित प्रावधान को वापस लेंगी।" कांग्रेस सदस्य ने केरल,

तमिलनाडु समेत देश के अनेक राज्यों में मनरेगा मजदूरों का बकाया वेतन देने के लिए केंद्र द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने का आरोप लगाया। विपक्षी दल की ही सांसद एस जोतिमणि ने आरोप लगाया कि इस सरकार में क्रमबद्ध तरीके से अल्पसंख्यकों को अलग-थलग किया जा रहा है। जोतिमणि ने यह दावा भी किया कि सरकार तमिलनाडु राज्यों जैसे राज्यों को आर्थिक 'ब्लैकमेल' के जरिए नियंत्रित करना चाहती है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदीशका पाल ने कहा कि संग्राम सरकार के समय भारत की छवि 'बनाना रिपब्लिक' की बन गई थी जिसे मोदी सरकार ने फिर से उभरती अर्थव्यवस्था बनाया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष



राहुल गांधी हमेशा "चीन की दुहाई" देते रहते हैं, लेकिन भारत की जीडीपी जहां 6.5 प्रतिशत है, वहीं चीन की जीडीपी केवल 4.6 प्रतिशत है। पाल ने कहा कि पहली बार इस सरकार ने संघीय ढांचे के तहत राजस्व व्यय में नहीं, पूंजी व्यय में

विश्वास किया है और वह पूंजी निर्माण में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पिछले साल की तुलना में 10.1 प्रतिशत पूंजी व्यय बढ़ाया है। भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013-2014 में अवसंरचना पर पूंजी व्यय जहां 1.9 लाख करोड़ रुपये था, वहीं आज यह 11.11 लाख करोड़ रुपये है। शिवसेना के धैर्यशील माने ने कहा कि 12 लाख रुपये की आय कस्मूक करने का सरकार का निर्णय क्रांतिकारी है जिससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि देश में आय असमानता बढ़ रही है और सरकार को विकसित भारत के लिए किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सपा की इकरा चौधरी ने कहा कि सरकार देश को 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रही है लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत दुनिया के कई देशों से पीछे है तो यह उपलब्धि फीकी साबित होगी।

कुणाल कामरा विवाद पर एकनाथ शिंदे बोले, ऐसे बयान के लिए ली 'सुपारी'

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के उनके खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कामरा ने 'सुपारी' लेने के बाद यह बयान दिया है। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सोमवार देर रात कहा कि वह आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं और अपने काम के जरिए इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।

कामरा का नाम लिए बिना उपमुख्यमंत्री ने कहा, "इस व्यक्ति ने सुपारी लेकर बयान दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और व्यंग्य कर सकते हैं। लेकिन, यह एक तरह से सुपारी लेकर बोलना है। मैंने मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन, कार्यकर्ताओं की तो भावनाएं होती हैं। इसी व्यक्ति ने पहले सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अर्नब गोस्वामी और उद्योगपतियों के बारे में बयान दिया था। ये सुपारी लेकर लगाए गए आरोप हैं, इसलिए मैंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं बोलूंगा भी नहीं। मैं अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।"

कामरा के बिना शर्त माफी मांगने की मांग पर शिंदे ने कहा, "मैं आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। तीन साल पहले जब से हमारी सरकार बनी है, लोग आरोप लगा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं आरोपों का जवाब काम से दूंगा। अगर हम आरोपों

का जवाब आरोपों से देने लगे, तो हम काम पर ध्यान नहीं लगा सकते। हमने आरोपों का जवाब काम से दिया, इसलिए लोगों ने हमें फिर से चुना। हमें 80 में से 60 सीटें मिलीं। ठाकरे की शिवसेना को सिर्फ 20 सीटें मिलीं।



शिंवसेना कार्यकर्ताओं के स्टूडियो में तोड़फोड़ के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैं तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करता। हमें यह भी देखना चाहिए कि आरोप लगाते समय दूसरा व्यक्ति किस हद तक गिरता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं संवेदनशील हूँ और मेरे पास सहन करने की बहुत शक्ति है। मैं किसी से बात नहीं करता और शांत रहता हूँ, काम करता हूँ, काम पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और लोगों को न्याय दिलाता हूँ। इसलिए हमें इतनी

बड़ी सफलता मिली है।"

बता दें, शिवसेना ने सोमवार को मुंबई के हैबिटेड कॉमेडी क्लब में कॉमेडियन कुणाल कामरा के हालिया प्रदर्शन के दौरान की गई 'अपमानजनक' टिप्पणी की कड़ी निंदा

भी घोषणा किया कि वह महाराष्ट्र के लोगों के लिए अथक प्रयास कर रहे नेतृत्व का अपमान या बदनाम करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें कहा गया, "हम मांग करते हैं कि कुणाल कामरा, एकनाथ शिंदे के खिलाफ

अपनी टिप्पणी के लिए बिना शर्त माफी जारी करें और नफरत और गलत सूचना फैलाने के लिए कॉमेडी का इस्तेमाल करना बंद करें।

कामरा के विवादास्पद और आक्रामक व्यवहार का इतिहास है, जो साबित करता है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। शिवसेना ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने व्यंग्य के बहाने बार-बार संस्थाओं, व्यक्तियों और धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है।

सिकंदर खेर तीन बैक-टू-बैक प्रोजेक्ट्स में व्यस्त

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सिकंदर खेर इन दिनों तीन बैक-टू-बैक प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। सिकंदर खेर इस समय अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं। वह एक के बाद एक तीन अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वह अपनी जबरदस्त अदाकारी से इंडस्ट्री के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक साबित हो रहे हैं। फिलहाल, वह श्रीराम राघवन की बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा इक्वीस, साकिब सलीम और हुमा कुरैशी निर्मित मजेंदार कॉमेडी बेबी डू डाई डू और रोमांटिक एंटरटेनर जस्सी वेड्स जस्सी की शूटिंग में व्यस्त हैं। आमतौर पर सिकंदर एक समय



में सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं, जिससे वह अपने किरदार पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। हालांकि, वह काम को मना करने में यकीन नहीं रखते और उन्हें मिल रहे इन अवसरों के लिए आभारी हैं। सिकंदर ने कहा, अभी मेरे पास यह सुविधा नहीं है कि मैं एक समय में सिर्फ एक ही फिल्म करूँ, लेकिन गलत मत समझिए, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहा हूँ... सेट पर रहना, काम करना और

मेरी फिल्में एवं शोज़ रिलीज़ होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस वक्त जो भूमिकाएं मैं निभा रहा हूँ, वे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और मैं इस प्रक्रिया का पूरा आनंद ले रहा हूँ। सच कहूँ तो यह और भी अच्छा होता, यदि तारीखें इतनी बेहतरीन तरीके से मैनेज हो जातीं कि कोई

भी शूट ओवरलैप न करे। लेकिन यह संभव नहीं है, और मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मैं बिजी हूँ और भगवान की कृपा रही तो यह सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। अपने इस दमदार लाइनअप के साथ, सिकंदर के फैंस उन्हें अलग-अलग अवतारों में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं, जहां वह अपने खास अंदाज़ और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं।

दूसरी बार मां बनी एमी जैक्सन, बेटे को दिया जन्म

मुंबई। बॉलीवुड में खुशियों की लहर है। अभिनेत्री आथिया शेडी और क्रिकेटर केएल राहुल के पेरेंट्स बनने के बाद ब्रिटिश मॉडल-अभिनेत्री एमी जैक्सन के घर भी किलकारी गूँजी है। दूसरी बार

महीने बाद बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद दोनों का ब्रेक अप हो गया था। बड़े बेटे का नाम उन्होंने एंड्रयूजस जैक्स रखा है। जॉर्ज से अलगाव के बाद एमी की मुलाकात साल 2022 में वेस्टविक से हुई।



मां बनी अभिनेत्री ने बेटे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने प्रशंसकों को जानकारी दी।

इंस्टाग्राम पर पति के साथ तस्वीरें शेयर कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "दुनिया में आपका स्वागत है, बेबी बॉय।" इसके साथ ही उन्होंने बेबी के नाम का भी खुलासा किया। बताया कि बेटे का नाम "ऑस्कर अलेक्जेंडर वेस्टविक" रखा है। शेयर की गई तीन तस्वीरों में से पहली तस्वीर में वह पति के साथ और दूसरी, तीसरी तस्वीर में वह अपने नन्हें राजकुमार को दुलारती नजर आईं।

ब्रिटिश एक्टर एड वेस्टविक और एमी जैक्सन का ये पहला बच्चा है। जबकि एक्ट्रेस के छह साल के बड़े बेटे के पिता होटल बिजनेसमैन जॉर्ज पानायियोटी हैं। 2019 में सगाई के आठ

दो साल बाद अगस्त में दोनों ने शादी कर ली थी। ब्रिटिश अभिनेता वेस्टविक के साथ शादी के दो महीने बाद प्रेग्नेंसी की खबर प्रशंसकों से शेयर की थी। ब्रिटिश अभिनेत्री-मॉडल एमी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह बॉलीवुड में कई फिल्मों कर चुकी हैं। वह अभिनेता अक्षय कुमार के साथ 'सिंह इज ब्लिंग' में काम कर चुकी हैं। सोनू सूद के साथ 'तूतक तूतक तूतिया' और विद्युत जामवाल, नोरा फतेही के साथ 'क्रैक' में भी काम कर चुकी हैं। वह दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपने अभिनय का कमाल दिखा चुकी हैं। रजनीकांत के साथ '2.0' में भी नजर आई थीं। 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'एक दीवाना' में उन्हें प्रतीक बब्बर के साथ देखा गया था। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई।

दीपिका ने भारतीय फिल्मों और टैलेंट को ऑस्कर में पहचान न मिलने पर दुख जताया

गाने नाटू-नाटू को अवॉर्ड मिलते समय भावुक हो गई

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लगता है कि भारत की कई ऐसी फिल्में थीं जो ऑस्कर अवॉर्ड जीत सकती थीं मगर उन्हें वे पहचान नहीं मिली। दीपिका इन दिनों लुई विटोन और कार्टियर के लिए वैश्विक लक्जरी फैशन हाउस द्वारा एंबेसडर के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। इसी वीडियो में दीपिका ऑस्कर पर बात करते हुए कहती हैं कि जब आरआरआर फिल्म के गाने नाटू-नाटू को अवॉर्ड मिला था वे मौके पर मौजूद थीं। पिछले कुछ समय में भारतीय फिल्मों ने ग्लोबल स्तर पर तारीफें बटोरी थीं। हालांकि, ऑस्कर 2025 की फाइनल सूची में इन फिल्मों को जगह नहीं मिल सकी थी। इस खबर ने कई भारतीयों का दिल तोड़ा था जिसमें दीपिका भी शामिल हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए दीपिका ने भारतीय फिल्मों और टैलेंट को ऑस्कर में पहचान न मिलने पर दुख जताया। दीपिका ने कहा, भारत को कई बार ऑस्कर से वंचित रखा गया है। <

कई ऐसी फिल्मों और टैलेंट हैं जो अवॉर्ड के हकदार थे, मगर उन्हें नजरअंदाज किया गया। हालांकि दीपिका ने उस पल को याद किया जब एस एस राजामौली की फिल्म आरआरआर को ऑस्कर मिला था। वे कहती हैं, मैं ऑडियंस में बैठी थी। जब आरआरआर के नाम का ऐलान हुआ, उस पल में



भावुक हो गई थी। यह मेरे लिए बेहद खास पल था। भले ही मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं थी, लेकिन एक भारतीय होने

के नाते यह जीत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। बता दें कि दीपिका ने 2023 के ऑस्कर समारोह में आरआरआर के

गाने नाटू नाटू को प्रेजेंट किया था। इस गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता था।